20 जून, संयुक्तांक (मार्च-जून), 2024 ☆ वर्ष 33, पृष्ठ संख्या 60, अंक 03-06

राजस्थान सुजस

नवयुग निरन्तर ... 3.0

मेवाड़ की गणगौर

मेवाड़ में होलिका दहन एवं रंगोत्सव के बाद गणगौर की पूजा शुरू होती है व शीतला सप्तमी पर पारम्परिक छोटी गणगौर का दो दिवसीय मेला भरता है। इसके लिए छोटी गणगौर, ईसर-पार्वती व कानूडे की प्रतिमाएं बनती हैं। उदयपुर शहर के मोती चौहट्टा क्षेत्र में शीतला सप्तमी पर छोटी गणगौर के मेले में महिलाएं गणगौर प्रतिमाएं खरीदती हैं, जिन्हें वे गीत गाती हुई सिर पर उठाकर ले जाती हैं। प्रत्येक वर्ष उदयपुर शहर की पिछोला झील के बंशी घाट से गणगौर घाट तक शाही ठाठ-बाट के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाती है।

आलेख एवं छाया : **जयेश पाण्डया**
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

प्रधान संपादक
सुनील शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
मोहित जैन

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिंटर्स

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80948-98098
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

वर्ष : 33 अंक 03-06 | **मार्च-जून (संयुक्तांक), 2024**

इस अंक में

लोक जीवन	2
संपादकीय	4
जल सहेजने की रीति अब प्रदेश नीति	6
संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना	8
देवास परियोजना	10
डिजिटल बाराबंदी सिस्टम	12
परम्परागत कुंड	14
जाखम बांध	16
पंचायत मौसम सेवा	20
यमुना जल	22
योग का महत्व	24
सहज योग	26
सर्व हित काजे, राम द्वारे ...	28
संसद में राजस्थान	37
दिल्ली डायरी	38
युवाओं का बढ़ा विश्वास	40
सामयिकी	42
अंगदान	46
प्रथम प्राथमिकता - सुरक्षित प्रदेश	48
हर घर बिजली	52
राहत : पेट्रोल-डीजल पर	56
Empowerment	57
पीएम श्री विद्यालय	58

प्रदेश में जल क्रांति का सूत्रपात 05

मेह सूं नेह ... 18

योग दिवस 23

हस्ताक्षर नवयुग निरन्तर ... 3.0 29

बांसवाड़ा का आम 50

प्रधानमंत्री कुसुम योजना 54

सोच समय से आगे ...

भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास को त्वरित गति देने वाले विज़नरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार पुन: भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अमृत संकल्प के साथ श्री नरेद्र मोदी द्वारा प्रवर्तित विकास का यह "नवयुग" निरन्तर है, जिसे देश ने 3.0 का नाम दिया है। अपने 71 सहयोगियों के साथ शपथ लेने के बाद श्री मोदी ने देश से कहा, "हमारी टीम के लिए न तो समय का बंधन है, न सोचने की सीमाएं और न ही पुरुषार्थ के लिए कोई तय मानदण्ड"।

उनकी यह भावना प्रदेश में भी साकार है जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दशकों से प्रदेशवासियों की अनुत्तरित समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था, जिम्मेदार प्रशासन, युवाओं की अपेक्षा-आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के लिए नवाचार, महिला-किसान-श्रमिकों के सशक्तीकरण के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और विधि का राज सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान सरकार सभी क्षेत्रों में प्रदेश के समस्त वर्गों को साथ लेकर कार्य कर रही है।

इसी तरह पानी का मोल हर राजस्थानी को पता है और पानी सहेजना भी यहां की संस्कृति में परम्पराओं से ही रचा-बसा है, लेकिन प्रदेश की प्यास बुझाने के लिए राज्य स्तर पर एक साथ इतने ठोस प्रयास पहली बार नजर आते हैं। तीस वर्ष से अटका यमुना जल समझौता इसकी बानगी है। शुष्क और मरूस्थलीय प्रदेश की छवि वाला हमारा प्रदेश इन्हीं प्रयासों से जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना, देवास परियोजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 कुछ ऐसे ही प्रयास हैं।रिकॉर्ड हीट वेब में बिजली के उत्कृष्ट प्रबन्धन के साथ ही भविष्य में किसानों और निवासियों के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता पर सरकार का पूरा फोकस रहा है।

स्वस्थ तन, स्वस्थ चेतन-अवचेतन के लिए योग भारत की ही देन है। इस वर्ष भी 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों ने भारत के ज्ञान और गौरव की वैश्विक प्रतिष्ठा को रेखांकित किया। ऐसे ही कुछ घटनाक्रमों को शामिल करता सुजस का मार्च-अप्रेल-मई-जून का यह संयुक्तांक आप सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

(सुनील शर्मा)
प्रधान सम्पादक

प्रदेश में
जल क्रांति का सूत्रपात

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 61 प्रतिशत मरूस्थल है, जबकि प्रदेश में उपलब्ध सतही जल देश में उपलब्ध कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। यहां सतही जल स्रोतों की कमी, वर्षा की मात्रा एवं निरंतरता में कमी और अत्यधिक भूजल दोहन से स्थिति चिंताजनक बनी रहती है। इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कठिनाइयों के बाद भी प्रदेश में हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार जलसंकट के स्थायी समाधान के लिए प्रदेशभर में गांवों और शहरों को जल उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए संकल्पित हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को वर्तमान और भविष्य के लिए शुद्ध पेयजल एवं किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में नई जल क्रांति का सूत्रपात किया है। इसमें केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है।

श्री शर्मा की इच्छाशक्ति व प्रयासों से आगे बढ़ी संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (पीकेसी-ईआरसीपी) के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जगह अब 21 जिले लाभान्वित होंगे। उधर मेवाड़ अंचल में उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण की सौगत प्रदेश को मिली, जिससे जिले की झीलें वर्ष पर्यन्त जल से लबालब रहेंगी। इसी तरह तीन दशकों से अटके यमुना जल समझौते से शेखावटी के सीकर, चूरू, झुंझूनूं एवं नीमकाथाना जिले को यमुना का पानी मुहैया कराने जैसे सपनों को साकार करने के लिए संबंधित राज्यों से समझौता किया गया है।

इतना ही नहीं, गांव-गांव को जलक्रान्ति की इस मुहिम से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश में 11 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20 हजार गांवों में टांके, नाडी जैसे 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया जाएगा। इससे प्रदेश के भूजल स्तर में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री के ये प्रयास और राजस्थान में जल क्षेत्र में हाथ में ली गई परियोजनाएं प्रदेश को नई जल क्रान्ति और जल उपलब्धता की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0

जल सहेजने की 'रीति' अब 'प्रदेश नीति'

11 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय कर बीस हजार गांवों में बनेंगे पांच लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

ग्रामवासियों से रात्रि चौपालों में होगी समूह चर्चा, मिलेगी सम्पूर्ण जानकारी

जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग तकनीकों का होगा उपयोग

सोनू शर्मा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां वर्षा के जल की एक-एक बूंद को अमृत के समान सहेजने की सीख देती हैं। बारिश के समय जब तालाब, कुएं व बावड़ियां पानी से लबालब हो जाते हैं तब वहां के निवासी उसे देवतुल्य समझ विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। राज्य सरकार ने भी इस रीति को अपनी नीति में शामिल कर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत कर वर्षा जल के संरक्षण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता पुन: दोहरायी है।

राज्य सरकार ने प्रदेश को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेखानुदान वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की है। अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनसहभागिता सुनिश्चित कर बावड़ियों, खड़ीन, तालाबों, झालरा, कुई, नाड़ी, झीलों आदि परंपरागत जल स्रोतों का निर्माण एवं उन्हें पुनर्जीवित करना है। अभियान के तहत 11 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।

इस वर्ष 5 हजार से अधिक गांवों का चयन

वर्ष 2024-25 में 5 हजार 135 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें मुख्यत: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक में स्वीकृत ग्राम प्राथमिकता से लिए गए हैं। साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस कर कार्य योजना तैयार की गयी है। जिला स्तरीय समिति में इस कार्य योजना का अनुमोदन जनप्रतिनिधियों से करवाकर कार्य सम्पन्न किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रशासनिक और जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे।

राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जल संसाधन, वित्त, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयोजना, जनजाति क्षेत्र विकास, वन एवं पर्यावरण, उद्योग, कृषि तथा राजस्व मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही मुख्य सचिव, कृषि, वन एवं पर्यावरण, वित्त, उद्योग, जनजाति क्षेत्र विकास, आयोजना, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव व दो विषय विशेषज्ञों को भी

सदस्य बनाया गया है जो इस अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग कर सुचारू क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक पर उपखंड अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच समिति के अध्यक्ष होंगे।

गांवों के चयन की प्रक्रिया

राजस्थान सरकार जल संकट के स्थाई समाधान के लिए प्रदेश भर में गांवों को जल उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में एमजेएसए 2.0 के तहत इस वर्ष राज्य के 349 ब्लॉक्स में 1 लाख 50 हजार परियोजनाओं का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य सम्पादित किये जायेंगे। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में चयनित गांवों का चयन कर कार्य किये जायेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा जल ग्रहण आधारित बजट घोषणा वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। गांवों का चयन बारानी कृषि क्षेत्र, मनरेगा के एक्टिव जॉब कार्ड, भू-जल स्तर, टैंकर आपूर्ति वाले गांव, बीपीएल सूचकांक, अकाल प्रभावित, अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिशत, लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत, जल जीवन मिशन में सम्मिलित नहीं हो सकने वाले गाँव, फ्लोराइड प्रभावित, SRSAC जोधपुर द्वारा तैयार वाटरशेड एटलस में दी गयी जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता अनुसार किया जायेगा।

अभियान में किये जाने वाले कार्य

जलग्रहण (कैचमेन्ट) क्षेत्र उपचार : डीप कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज (डीप सीसीटी) कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज (सीसीटी), स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेज, फार्म पौण्ड, छोटे बांध यथा-मिनी परकोलेशन टैंक (एमपीटी)/अर्दन चेक डेम/खड़ीन/जोहड़, टांका निर्माण, एनिकट, पक्का चेकडैम, गैबियन, कन्टूर/फील्ड बण्ड, ड्राईस्टोन मेसेनरी पॉण्ड, गली प्लग, लूज स्टोन चेक डेम, पीआरटी, डिग्गी, जल हौज, खेत तलाई, संकन पॉण्ड, तालाब, तलाई।

नाला उपचार (ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेन्ट) : श्रृंखलाबद्ध छोटे-छोटे एनिकट, मिट्टी/ सीमेन्ट के चेकडेम, परकोलेशन टैंक, मिनी परकोलेशन टैंक (एमपीटी), माइक्रो स्टोरेज टैंक, सब सरफेस बेरियर, पक्के एनिकट, माइक्रो स्टोरेज टैंक।

लघु, बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, सिंचाई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने हेतु नहरों धोरों/वाटर कोर्स/फील्ड चैनल आदि के निर्माण/मरम्मत के कार्य एवं जल स्रोतों व संरचनाओं को नालों से जोड़ने का कार्य, नहर से सिंचाई हेतु फील्ड चैनल निर्माण व मरम्मत, मिनी इरिगेशन टैंक।

जल संग्रहण ढांचों की क्षमता बढ़ाना : मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, नालों को गहरा एवं चौड़ा करना, नाला स्थरीकरण, पैरीफेरल बण्ड, बैंक स्टेबलाइजेशन, डायवर्जन चैनल।

पेयजल स्रोतों को सुदृढ़ीकरण करने के कार्य, सार्वजनिक कुओं की मरम्मत/ पुनरूद्धार, कुएं एवं ट्यूबवैल/हैण्डपम्प तथा कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के पुनर्जलभरण का कार्य, रेन वाटर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, भू जल रिचार्ज शाफ्ट, बावड़ी, चरागाह विकास, वृक्षारोपण एवं उद्यानिकी, सूक्ष्म सिंचाई यथा ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं पाइपलाइन आदि, भू-जल स्तर नापने के लिए पीजो मीटर स्थापित करना जैसे विभिन्न कार्य किये जायेगे।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 हेतु जिला जल संचयन कार्य योजना

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा तैयार की जाएगी।
- प्रतिवेदन को भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) एवं रिमोट सेसिंग का उपयोग कर वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया जायेगा।
- परियोजना तैयार करने से पूर्व मोबाइल एप के माध्यम से क्षेत्र का सर्वेक्षण कर समस्त कुओं, ट्यूबवेल, जल संग्रहण ढांचों, हैंडपंप आदि को जिओ टैग किया जायेगा।
- टैगिंग के समय ग्रामवासियों को साथ रखा जायेगा एवं रात्रि चौपालों में समूह चर्चा कर उन्हें सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी।
- अनुमोदित डीपीआर को ग्रामसभा में ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्राप्त सुझावों के साथ डीपीआर ब्लॉक स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में चयन से लेकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी होने तक की समस्त समीक्षा नोडल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना के आधार पर की जाएगी। जीआईएस तकनीक के द्वारा रियल टाइम बेसिस पर समीक्षा हेतु सभी जल संरक्षण कार्यो के अक्षांश एवं देशान्तर मय फोटोग्राफ स्मार्ट मोबाइल फोन आधारित एप से रियल टाइम बेसिस पर अपलोड किए जायेंगे। राज्य स्तर एवं जिला स्तर से नामित कार्मिकों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान दिए गए सुझावों को जिला कलक्टर द्वारा उनकी अनुपालना संबंधित विभागों के माध्यम से सुनिश्चित करवाई जाएगी।

बावड़ी

जोहड़

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना

आकार ले रहा मरुधरा का खुशहाल भविष्य

भगीरथ की भूमिका में मुख्यमंत्री

दिनेश शर्मा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

तरक्की के नये अध्याय लिख रही मरूधरा के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना एक ऐतिहासिक कदम है। विगत जनवरी माह में जब इस अति महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच एमओयू हुआ तो राजस्थान के खुशहाल भविष्य की दिशा में एक और स्वर्णिम अध्याय की शुरूआत हुई। इस परियोजना के मूर्त रूप लेने से पूर्वी राजस्थान में पानी की पर्याप्त उपलब्धता होगी, जिससे प्रदेश का कायापलट होगा।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयास इस परियोजना को साकार करने की दिशा में भगीरथ की भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को नदी जोड़ो परियोजना में समाहित किया गया है, जो अब संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के नाम से मूर्त रूप लेगी। परियोजना का बजट 37 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 45 हजार करोड़ रुपये किया गया है। ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद इसे शीघ्र धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में केन्द्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये परियोजना जब मूर्त रूप लेगी तो पूर्वी राजस्थान की अधूरी आस पूरी होगी और प्रदेश के विकास को नए पंख लगेंगे।

क्या हैं प्रदेश के लिए मायने?

धोरों की धरती राजस्थान हमेशा पानी की कमी से जूझता रहा है। देश के सतही जल का महज 1.16 प्रतिशत और भूमिगत से जल का सिर्फ 1.72 फीसदी राजस्थान के हिस्से में आता है। जबकि देश की 5.67 प्रतिशत आबादी यहां निवास करती है और राज्य में देश का 10.41 प्रतिशत भू-भाग है। ऐसे में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना प्रदेश को पानी के मामले में समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। 28 जनवरी 2024 को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय एमओयू के अनुसार इस संशोधित परियोजना में राजस्थान राज्य हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर राठौड़ बैराज, बनास नदी पर डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध और

मौजूदा 26 टैंकों का नवीनीकरण शामिल है। परियोजना के मूर्त रूप लेने से राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश के भी विकास की राह प्रशस्त होगी।

विस्तृत होगा दायरा

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (ईआरसीपी) का दायरा अब पहले से ज्यादा विस्तृत होगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए तैयार की गई इस परियोजना में अब 21 जिले कवर होंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ब्यावर, अजमेर एवं केकड़ी जिले को परियोजना का लाभ मिलेगा। इन जिलों की लगभग 3.50 करोड़ आबादी को इस परियोजना से अगले 5 दशक तक पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। केन्द्र सरकार ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी को प्रमुख प्राथमिकता वाली 5 लिंक परियोजनाओं में शामिल किया है, जिससे इस योजना पर त्वरित गति से कार्य होगा। परियोजना में अब 90 प्रतिशत फंडिंग केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी और केवल 10 प्रतिशत अंशदान ही राज्य सरकार को वहन करना होगा। आजादी के बाद यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना होगी। जबकि, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के बाद देश की यह दूसरी नदी लिंक परियोजना है।

बदल जाएगी प्रदेश की तकदीर और तस्वीर

परियोजना की डीपीआर में शामिल 26 बांधों के अलावा इसमें 122 बांधों को और जोड़ा जाएगा। इस प्रकार ये परियोजना समूचे पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। इससे क्षेत्र में पेयजल की बरसों पुरानी समस्या का समाधान तो होगा ही, प्यासे खेतों को सिंचाई का भरपूर पानी मिलने से धरती सोना उगलेगी। तकरीबन 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए इस परियोजना से पानी मिलेगा। लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने से फसल उत्पादन, किसानों की आय और खुशहाली बढ़ेगी। साथ ही, उद्योगों को भी उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी मुहैया हो पाएगा। प्यासे खेतों और सूखे कंठों तक जब पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचेगा तो धोरों की धरा पर खुशहाली की फसल लहलहाएगी।

ये कार्य भी हैं प्रस्तावित

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अलवर व अजमेर जिलों में बांध, पूर्व निर्मित कालीसिंध बांध के फेज-2 में जल भराव क्षमता बढ़ाने का कार्य एवं कालीसिंध बांध से ग्रेविटी फ्लो द्वारा सीधे गलवा बांध में जल ट्रांसफर किये जाने के लिए नहर तंत्र प्रस्तावित है। वहीं, बनास नदी पर सवाईमाधोपुर जिले के बारनवाड़ा में पिकअप वियर और बाणगंगा नदी पर भू-जल पुनर्भरण के लिए दौसा के टुड़ियाना में रिचार्ज रिजर्वायर को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार, भरतपुर जिले में बंध बरेठा बांध से ऐतिहासिक महत्व की सुजान गंगा में तथा अजमेर जिले में प्रस्तावित बांध से पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर के सरोवरों में पानी डाला जाना प्रस्तावित किया गया है। परियोजना से 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

डीपीआर करवाई जा रही तैयार

एमओयू होने के साथ ही इस महत्वपूर्ण परियोजना पर तत्काल प्रभाव से कार्य भी शुरू हो गया है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना की डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के निर्देशन में बनाई जा रही है। राजस्थान क्षेत्र की डीपीआर वैप्कोस द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के सहयोग से तैयार की जा रही है। डीपीआर के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम द्वारा संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना में सम्मिलित किये जाने वाले सभी घटकों से संबंधित सर्वे, एलाइमेंट, डाटा एवं विभिन्न घटकों की डीपीआर वैप्कॉस को उपलब्ध करवा दिये गए हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के अभियन्ताओं द्वारा सतत रूप से वैप्कोस कार्यालय में परियोजना के राजस्थान भाग की डीपीआर तैयार कराई जा रही है।

तेज गति से हो रहा कार्य

परियोजना से राजस्थान के 21 जिलो में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्रोतों का चिन्हिकरण किया जा चुका है। विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी की नियुक्ति के लिए 7 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्यों के लिए आवश्यक भूमि अवाप्ति के क्रम में निगम द्वारा प्रस्तुत भूमि अवाप्ति प्रस्ताव पर संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा कमेटी का गठन किया जा चुका है। प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्यों के लिए 132 गांवों की लगभग 6409 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की जानी है जिसके लिए 13 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। पूर्वी राजस्थान में पेयजल की आवश्यकता पूर्ति के लिए परियोजना के प्रथम चरण में बनास नदी पर सवाई माधोपुर जिले की खण्डार तहसील में डूंगरी बांध एवं चौथ का बरवाड़ा तहसील में राठौड़ बैराज के निर्माण के लिए निगम अधिकारियों ने मौके पर आवश्यक सर्वे पूर्ण कर लिया है तथा तकमीना बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

देवास परियोजना
प्राचीन जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन का आधुनिक संस्करण

उदयपुरवासियों को मिली देवास तृतीय व चतुर्थ चरण की सौगात
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही किया था 1690 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास

विनय सोमपुरा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान के दक्षिणांचल में अरावली की उपत्यकाओं के मध्य स्थित मेवाड़ प्राचीनकाल से ही वर्षा जल संचय और जल प्रबंधन की मिसाल रहा है। रियासत काल में राणाओं और महाराणाओं ने दूरदर्शिता के साथ यहां के जलाशयों के निर्माण और नदियों को जोड़ने के गंभीर प्रयास किए, इसकी बदौलत सदियों बाद भी उदयपुर में पेयजल संकट के हालात नहीं बनते हैं। संभवतया जल प्रबंधन के इससे अच्छे प्राचीन उदाहरण और कहीं नहीं मिलते हैं। वर्तमान दौर में उदयपुर की जीवन रेखा बन कर उभरी देवास परियोजना उसी रियासतकालीन जल संरक्षण और जल प्रबंधन सोच का आधुनिक संस्करण कही जा सकती है। राज्य सरकार ने हाल ही उदयपुर को देवास परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ चरण की सौगात दी है। गत 1 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1690 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास किया है। यह परियोजना आने वाले दशकों में उदयपुरवासियों की प्यास बुझाने में सहायक सिद्ध होगी।

देवास परियोजना : अब तक

उदयपुर शहर की तत्कालीन पेयजल आपूर्ति मांग सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1973-74 में देवास- प्रथम (गोराणा बांध) का निर्माण किया गया, जिसकी सकल क्षमता 120 एमसीएफटी है। वर्ष 2011 में उदयपुर शहर की पेयजल मांग अनुसार देवास द्वितीय परियोजना की परिकल्पना की गई। देवास द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत ही मादडी बांध (कुल क्षमता 85 एमसीएफटी) का निर्माण किया गया। इससे निकलने वाली 1.21 किलोमीटर की सुरंग को आकोदडा की मुख्य सुरंग से जोड़ा गया। देवास द्वितीय के अंतर्गत 302 एमसीएफटी क्षमता का आकोदडा बांध का निर्माण किया गया। इससे 11.05 किलो मीटर लम्बी सुरंग का निर्माण कर बांध से उदयपुर शहर की पिछोला झील में 550 एमसीएफटी वार्षिक जल अपवर्तन की योजना बनाई गयी। उक्त परियोजना वर्ष 2015 मे पूर्ण कर ली गयी।

देवास परियोजना : तृतीय एवं चतुर्थ चरण

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2031 की उदयपुर शहर की जनसंख्या 875874 तक होने का अनुमान है। इसके अनुसार कुल 2397 एमसीएफटी वार्षिक पेयजल मांग के विपरीत 1738 एमसीएफटी वार्षिक पेयजल ही उपलब्ध है। जनसंख्या वृद्धि की गणनानुसार यह मांग वर्ष 2036 तक 2613 एमसीएफटी हो जाएगी। अत: भविष्य की पेयजल मांग की पूर्ति हेतु देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना तैयार की गई है। देवास तृतीय परियोजना के अन्तर्गत उदयपुर जिला के गोगुन्दा तहसील के नाथियाथाल गांव के निकट 703 एमसीएफटी क्षमता का देवास तृतीय बांध का निर्माण करवाया जाएगा। इससे 11.04 लम्बी सुरंग का निर्माण कर देवास द्वितीय (आकोदडा बांध) में जल अपवर्तन किया जायेगा।

पूर्व निर्मित आकोदडा बांध एवं सुरंग से उदयपुर शहर की पिछोला झील में जल अपवर्तन होगा। देवास चतुर्थ परियोजना के अन्तर्गत गोगुन्दा तहसील के अम्बावा गांव के निकट 390 एमसीएफटी क्षमता का देवास चतुर्थ बांध का निर्माण कर इससे 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर, देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाएगा। जिससे जल देवास चतुर्थ बांध से देवास तृतीय बांध में

अपतर्वन किया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार देवास द्वितीय (आकोदडा बांध) एवं सुरंग के माध्यम से पिछोला झील में जल अपवर्तन किया जा सकेगा। देवास तृतीय एवं चतुर्थ में कुल 156.18 हैक्टेयर वन भूमि आ रही है। वहीं कुल 133.45 हैक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की अनुमानित लागत 1690.55 करोड़ है एवं 44 माह की समयावधि में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इससे 1000 एमसीएफटी वार्षिक जल अपतर्वन उदयपुर शहर की झीलों में किया जा सकेगा।

सर्वे एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ

जल संसाधन विभाग के अनुसार देवास तृतीय एवं चतुर्थ चरण के तहत बांध निर्माण के कार्य का कार्यादेश 396.93 करोड़ रुपये का मैसर्स दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड भोपाल को जारी किया गया, तथा सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। टनल निर्माण कार्य का 432.74 करोड़ रुपये का कार्यादेश मैसर्स मेघा इन्जीनियरिंग लिमिटेड हैदराबाद को जारी किया गया, तथा सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अलावा बांध एवं टनल निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

19वीं सदी में ही हो गई थी नदियों को जोड़ने की पहल

मेवाड़ में जल संरक्षण और जल प्रबंधन के विश्व में सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। यहां सदियों पहले से ही वर्षा जल को वृहद् स्तर पर सहेजने

की शुरुआत हो चुकी थी। अरावली की पहाड़ियों से पश्चिम की ओर बहने वाले पानी को सहजने के लिए थोड़ी-थोड़ी दूर पर तालाब बनाए गए। मदार बड़ा और मदार छोटा तालाब भरने के बाद इनका पानी थूर की पाल से चिकलवास पिकअप वियर से मदार नहर होते हुए फतहसागर झील को भरता है। मदार नहर की क्षमता से ज्यादा पानी आने पर चिकलवास पिकअप वियर से आयड़ नदी होते हुए मदार का पानी उदयसागर पहुंचता है। पानी की आवक ज्यादा होने पर स्वरूप सागर लिंक नहर से फतहसागर भरा जाता है। बड़ी तालाब के छलकने पर इसका पानी भी फतहसागर में पहुंचता है। पिछोला और फतहसागर भरने के बाद पानी गुमानिया नाल से आयड़ नदी होते हुए उदयसागर पहुंचता है। यहां से पानी बेड़च नदी होते हुए वल्लभनगर बांध को भरता है उसके बाद पानी चित्तौड़ जिले में स्थित बड़गांव बांध और घोसुंडा बांध को भरता है। इन बांधों की पूर्ति होने के बाद उदयपुर की झीलों से पानी बनास नदी होते हुए बीसलपुर बांध पहुंचता है।

इसके अलावा नदियों को जोड़ने की पहल भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम मेवाड़ में हुई। तत्कालीन महाराणा फतहसिंह ने वर्ष 1890 में उदयपुर शहर से 6 किलोमीटर दूर चिकलवास गांव के समीप आहड़ नदी पर एक बांध बनवाया। वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतहसागर झील तक पहुंचाने के लिए चिकलवास नहर का निर्माण किया। इसके अलावा राणा राज सिंह 'प्रथम' ने तीर्थ स्थल उबेश्वर क्षेत्र से निकलने वाली उबेश्वर नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया। इस प्रकार यह जल जनासागर तथा फतह सागर में पहुंचा। उदयपुर शहर में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमर कुण्ड, कुम्हारिया तालाब, रंगसागर, स्वरूप सागर तथा फतहसागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबन्धन की दृष्टि से विश्व भर में श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

विदेशी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा जल प्रबंधन कौशल

मेवाड़ के जल प्रबंधन कौशल को विदेशी जल वैज्ञानिकों के दल ने भी स्वीकारा है। वर्ष 2021-22 में उदयपुर आए वैज्ञानिकों के दल ने अपने अध्ययन में पाया कि मेवाड़ में सदियों पहले जिस दूरदर्शिता के साथ जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम हुआ, वह अद्भुत है। यहां हर साल 6328 एमसीएफटी वर्षा जल सहेजा जाता है, जो अपने आप में अनूठा उदाहरण है। मदार बड़ा तालाब की भराव क्षमता 84 एमसीएफटी, मदार छोटा की 30, बड़ी तालाब की 371, देवास प्रथम की 126, आकोदडर की 302, मादड़ी की 85, फतहसागर की 427, पिछोला की 483, गोवर्धन सागर की 9, उदयसागर की 1100, वल्लभनगर बांध की 1076, बड़गांव की 1112 तथा घोसुंडा की 1123 एमसीएफटी है।

जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए जलशक्ति मंत्रालय एवं इलेट्स टेक्नोमीडिया की ओर से आयोजित नेशनल वाटर इनोवेशन समिट एंड अवार्ड्स कार्यक्रम में उदयपुर जिले को उत्कृष्ट वर्षा जल संग्रहण के लिए नेशनल वॉटर इनोवेशन अवॉर्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उदयपुर में सफल व परिणाम मूलक प्रयोग के बाद जल प्रबंधन मे जन भागीदारी बढ़ाने के माय वेल मोबाइल एप को जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर के लिए जारी किया है।

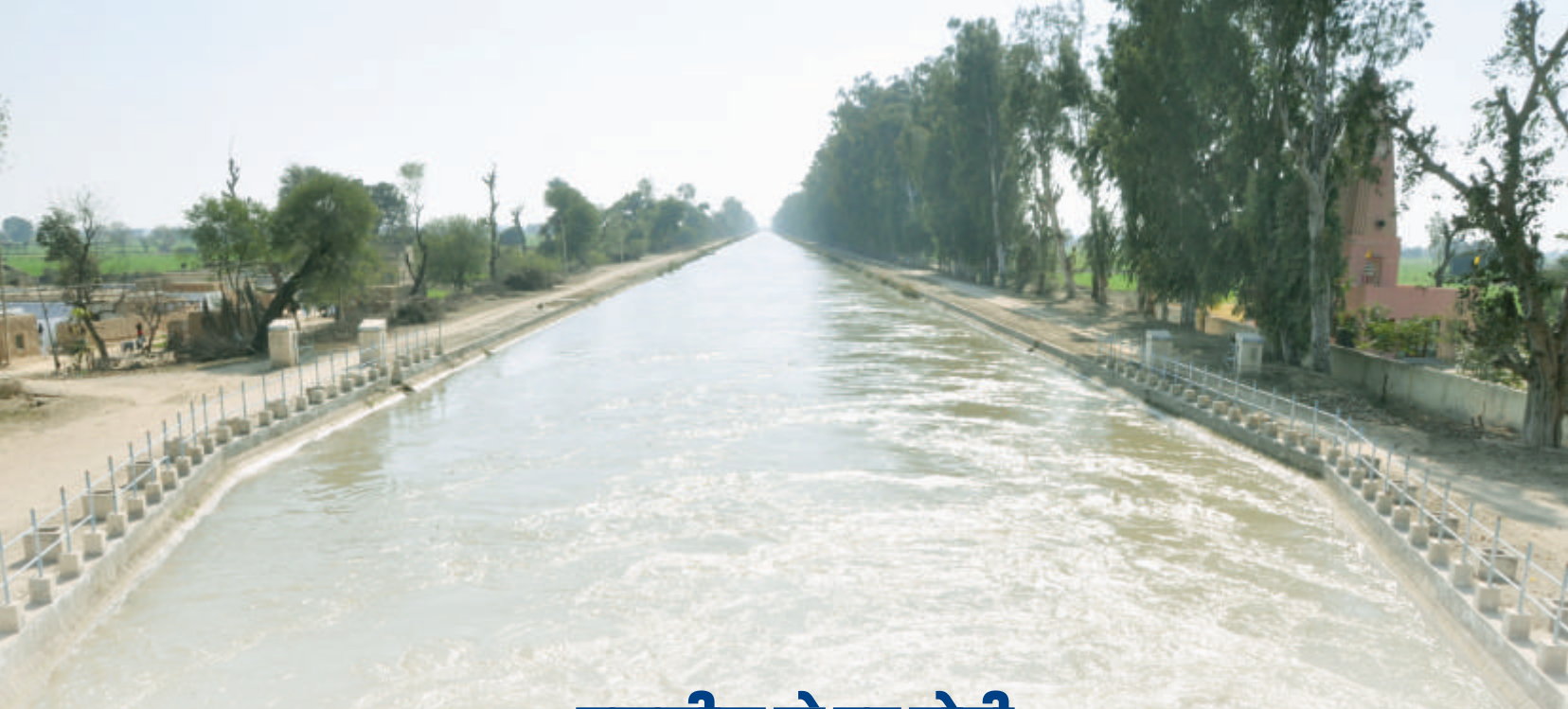

तकनीक से दूर होगी सिंचाई जल आवंटन की उलझन

डिजिटल बाराबंदी तंत्र से किसानों को ऑनलाइन मिलेगी सिंचाई पानी बारी की पर्ची

अनिल शाक्य
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

खाद्यान्न उत्पादन में योगदान के कारण प्रदेश के "धान के कटोरे" की उपमा से नवाजे गए श्री गंगानगर की पहचान कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीक के लिए भी बन रही है। इसी पहचान को और पुख्ता करने के लिए श्रीगंगानगर जिला कलक्टर श्री लोकबंधु की पहल पर पिछले दिनों जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम ने किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए नवाचार करते हुए डिजिटल बाराबंदी सिस्टम तैयार किया है।

आसान शब्दों में कहें तो यह जल संसाधन विभाग से अनुमोदित सूची के अनुसार दिन, अवधि और आपूर्ति के समय को दर्शाते हुए बारी-बारी से सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने वाले किसानों को जल आवंटित करने की प्रणाली है। डिजिटल सिस्टम की मदद से जहां एक ओर किसानों की सिंचाई जल वितरण की समस्याएं दूर हो सकेंगी, वहीं वितरण में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। यह नवाचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अपनाई गई तकनीक से सिर्फ गंगानगर ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों के किसान भी भविष्य में लाभान्वित हो सकेंगे।

दरअसल, गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया डिजिटल बाराबंदी सिस्टम सिंचाई जल वितरण समस्याओं के निराकरण का ही प्रयास है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा इस हेतु प्रयासरत हैं कि प्रदेश के किसानों को खाद, बीज से लेकर सिंचाई, पानी के लिये परेशान न होना पड़े।

डिजिटल बाराबंदी तंत्र

प्रवाहपूर्ण पारदर्शिता के साथ किसानों का सशक्तिकरण

इसलिए नहरों से होकर सिंचाई के पानी के खेतों तक पहुंचने के दौरान उपजने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जिला कलक्टर श्री लोकबंधु के मार्गदर्शन में जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की जिला स्तरीय टीम ने बाराबंदी सिस्टम को अमलीजामा पहनाया। महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुए इस बाराबंदी सिस्टम का उद्देश्य किसानों के लिए सिंचाई के मैनुअल शैड्यूल और पानी के हिस्से को डिजिटल रूप से संधारित करते हुए स्थानीय जल उपयोगिता संघों (वाटर ड्रिस्टीब्यूटरी एसोसिएशन) के लिए डिजिटल डेटाबेस बनाना है।

कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से तय होती है पानी की बारी

नहरी क्षेत्रों में किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पानी की बारी सीसीए (कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र) से तय होती है। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम-2000 क्रियान्वयन के तहत जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों द्वारा कमांड क्षेत्र के अनुसार चकों में किसानों की पानी की बारी उनके खेतों के क्षेत्रफल के हिसाब से तय की जाती है। जल संसाधन इसका नोडल विभाग है। आमतौर पर 200 से 250 हैक्टेयर वाले किसान की बारी 7 से लेकर 9 मिनट तक होती है। क्षेत्रफल कम-ज्यादा होने से बारी की टाइमिंग घटती-बढ़ती है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपयोगकर्ता संघ होगा, जिसमें सभी जल उपयोगकर्ता शामिल होंगे जो ऐसे क्षेत्र में भू-स्वामी के रूप में सदस्य हैं।

जल संसाधन विभाग श्रीगंगानगर के स्काडा नियंत्रण कक्ष में गत 29 अप्रेल को डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का लोकार्पण हुआ। जिला कलक्टर श्री लोकबंधु ने बताया कि पहले इस काम को मैनुअल किया जाता था, जिससे कई दफा किसानों को परेशानी रहती। अब बाराबंदी सिस्टम ऑनलाइन होने से प्रत्येक किसान को उसके सिंचाई पानी की स्थिति का सही पता लग सकेगा। इससे मैनुअल सिस्टम के दौरान होने वाली मानवीय भूल पर रोक लगेगी और पारदर्शिता के साथ-साथ किसानों को नियमानुसार सिंचाई पानी का आवंटन संभव होगा।

श्री लोकबंधु के अनुसार डिजिटल बाराबंदी सिस्टम प्रभावी होने से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। सिंचाई जल वितरण में पारदर्शिता बढ़ने से उनकी पैदावार तो बढ़ेगी ही, सिंचाई पानी की बारी के दौरान आने वाली परेशानियां भी दूर हो सकेंगी। आमतौर पर कृषि प्रधान जिला होने की वजह से किसान कई बार सही मात्रा में पानी नहीं मिलने या उनकी बारी कटने की शिकायत करते हैं। पर अब बाराबंदी सिस्टम की ऑनलाइन व्यवस्था होने से उनकी ये शिकायत और परेशानी दूर हो सकेंगी।

उनका मानना है कि बाराबंदी सिस्टम के पूरी तरह से प्रभावी होने के बाद किसान किसी भी चक (क्षेत्र) की सिंचाई बारी की सूचना कभी भी, कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चयनित चक की बाराबंदी केवल एक बटन के क्लिक से बनाई जा सकेगी और किसान अपनी सिंचाई बारी की पर्ची पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। जल संसाधन, कृषि सहित अन्य विभागों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा किसानों तक बाराबंदी सिस्टम की जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता जताते हुए श्री लोकबंधु कहते हैं-जिला प्रशासन के प्रयास रहेंगे कि बाराबंदी पोर्टल को शत-प्रतिशत पारदर्शीपूर्ण तरीके से क्रियान्वित करते हुए किसानों की सिंचाई जल वितरण की समस्याओं को दूर कर सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पोर्टल से न केवल किसान अपनी मौजूदा स्थिति और उनके खेतों तक पहुंचने वाले पानी की टाइमिंग के बारे में अपडेट होंगे बल्कि इसमें मानवीय गलती की गुंजाइश भी कम हो सकेगी।

जल संसाधन विभाग (उत्तर) के चीफ इंजीनियर श्री अमरजीत मेहरडा भी बाराबंदी पोर्टल को किसानों के लिए उपयोगी बताते हुए कहते हैं कि इसके प्रभावी होने के बाद जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष द्वारा किसानों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर केवल एक बार दर्ज करनी होगी। इसके बाद किसानों को सिंचाई बारी की पर्ची ऑनलाइन माध्यम से मिल सकेगी।

बाराबंदी सिस्टम की ज्यादा जानकारी देते हुए जल संसाधन विभाग श्रीगंगानगर के अधीक्षण अभियंता श्री धीरज चावला बताते हैं कि हर तरह से यह पोर्टल किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा। किस चक में कब पानी की बारी रहेगी, प्रति बीघा कितनी बारी है भराई-कटाई इत्यादि से लेकर किस किसान की बारी कब आएगी जैसे कई सवालों के जवाब ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। किसान इसके लिए पहले जल उपयोगिता अध्यक्षों और अधिकारी-कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब ये जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेंगी।

बाराबंदी सिस्टम डिजाइन करने वाले श्री परमजीत सिंह के शब्दों में- लंबे समय तक मैनुअल शैड्यूलिंग से जल वितरण प्रणाली का कामकाज होता रहा है, जिसमें अक्सर पारदर्शिता की कमी के चलते किसान समय पर पानी न मिलने की शिकायतें करते रहे हैं। इनसे निपटने के लिए ही डिजिटल सिस्टम बनाया है।

इस नई प्रणाली के बारे में पदमपुर तहसील के गांव 15 बीबी और श्रीगंगानगर तहसील के गांव 17 जैड के किसानों का कहना है कि सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण से न केवल जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होगी बल्कि वितरण में भी सुधार होगा। पहले की मैनुअल प्रणाली में कई बार पक्षपात की संभावना रहती थी। यह आधुनिक जल वितरण प्रणाली क्षेत्र के स्थानीय किसानों के लिए एक वरदान होगी क्योंकि पोर्टल के माध्यम से किसान ऑनलाइन ही अपनी सिंचाई बारी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनका समय, धन और श्रम बचेगा।

परम्परागत कुंड

बरसाती जल संग्रहण, संरक्षण एवं उपयोग का नायाब नमूना

कुमार अजय
सहायक निदेशक

यूं तो लगभग पूरा राजस्थान ही पेयजल के संकट से जूझता आया है। 'घी ढुळ्यां म्हारो कीं नीं जासी, पाणी ढुळ्यां म्हारौ जीव बळ जासी' जैसी कहावत आखिर यूं ही नहीं बनी। कोसों दूर से पानी के घड़े सिर पर लाती महिलाओं के चित्र रेगिस्तान की आंखों में बसे हैं। ऐसे में समूचे राजस्थान के ही लोगों ने अपनी-अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बरसाती पानी को सहेजने और उपयोग में लेने के अलग-अलग तरीके निकाले।

चूरू जिले के छोटे से गांव श्योदानपुरा में यूं तो महज 190 घरों की आबादी है लेकिन जल संरक्षण के लिहाज से यह गांव बड़ा संदेश देता आ रहा है। दो सौ से भी कम घरों वाले इस गांव में बरसाती पानी के करीब 300 कुंड हैं। यही नहीं, विभिन्न योजनाओं में करीब तीन दर्जन कुंड और बन रहे हैं। इस किसान बहुल गांव में बरसात के 'पालर पाणी' का यह उपयोग और संरक्षण जल बचाने के अभियान को राह दिखाने वाला है।

पेयजल संकट से निजात पाने के लिए शुरू हुआ कुण्ड निर्माण अब यहां एक मुहिम बन चुका है। गांव के ज्यादातर घरों में कुण्ड हैं। इसके अलावा अपने खेतों में कुण्ड बनाने वाले ग्रामीणों की संख्या भी अच्छी-खासी है। कुछ सक्षम लोगों ने एक से अधिक कुण्ड भी बना रखे हैं। जिन लोगों के घरों में कुण्ड नहीं हैं, वे गांव में बने सार्वजनिक कुण्डों का इस्तेमाल करते हैं।

जल संरक्षण से जुड़ी यह दास्तान केवल गांव श्योदानपुरा की नहीं, अपनी धरती में खारा जल संजोये चूरू जिले के लगभग हर गांव और ढाणी की कहानी है। जिले के गांव-गांव, घर-घर में बरसाती पानी के संरक्षण के लिए बनाए गए ये परम्परागत कुंड यहां के लोगों की दूरदृष्टि और जल विमर्श के परिचायक हैं। शुरू में पीने के पानी की समस्या और गांव के कुओं में खारा पानी होने के कारण लोग कुण्ड बनाने के लिए प्रेरित हुए। बाद में जलग्रहण योजनाओं, मनरेगा समेत अनेक योजनाओं में भी बड़ी संख्या में कुंड बने हैं। गांवों में सार्वजनिक कुण्ड तो सरकारी योजनाओं में बने ही, निजी कुण्डों के निर्माण में भी ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया।

नाडी, खड़ीन, बावड़ी, झालरा, जोहड़, तालाब, बेरी, झीलें, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इसी जल संरक्षण परम्परा का नमूना है। इसी सिलसिले में चूरू अंचल कुंड-बावड़ियों के निर्माण से जल संरक्षण के मामले में समूची दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत बना है। क्षेत्र में जल संरक्षण के ये संस्कार इतने रचे-बसे हैं कि पेयजल कुण्ड और जोहड़ के बिना किसी गांव और ढाणी की कल्पना ही सम्भव नहीं। श्योदानपुरा के अलावा भी दूधवाखारा, बास जैसे का घांघू, भामासी, बरड़ादास, लंबोर छिंपियान, बांय, मेहरी, बूंटिया, बूचावास, सिरसला, लाखाऊ समेत अनेक गांवों में घरों के अलावा, गांव से बाहर की तरफ और सार्वजनिक जगहों पर बड़े-बड़े कुंड अनायास ही दिखाई दे जाते हैं। गांवों में बहुतायत से बने ये कुंड बरसाती पानी के संग्रहण, संरक्षण और समुचित उपयोग का एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आते हैं।

समय के साथ आया तकनीक में बदलाव

खारे भूजल एवं पेयजल संकट के कारण बरसाती पानी के संग्रहण, संरक्षण एवं उपयोग के लिए कुंड निर्माण की परम्परा क्षेत्र में बहुत पुरानी है लेकिन समय के साथ तकनीक व सुविधाओं में काफी बदलाव आया है। श्योदानपुरा गांव के रणजीत गेट बताते हैं कि पुराने समय में कच्चे पत्थरों को जलाकर तैयार किए गए चूने से कुंड निर्माण किया जाता था और कुंड की छत भी उन्हीं पत्थरों और चूने से तैयार की जाती थी, जिसे ढोला कहा जाता है। कैचमेंट एरिया के तौर पर एक आंगन (पायतन) बनाया जाता था, जिससे बरसात का पानी कुंड में जाता था। टांका प्राय: गोल आकार में ही बनाया जाता था लेकिन हवेलियों आदि में चौकोर टांके भी बनाये जाते थे। वर्तमान में चूने-पत्थर की जगह सीमेंट और ईंटों ने ले ली है तथा छत भी पत्थर की पट्टियों से बनाई जाने लगी है। छत में आमतौर पर एक ढक्कन का प्रावधान है, जिससे जल निकासी होती है तथा जरूरत पड़ने पर साफ-सफाई आदि भी की जा सकती है। गरीब तबके के लोग ऊपर से खुला टांका भी बनाते रहे हैं, जिसे सूखी झाड़ियों, टहनियों से ढ़कते रहे हैं लेकिन सरकारी योजनाओं में कुंड निर्माण शुरू होने के बाद इस तरह के टांके (कुंड) अब कम ही दिखाई पड़ते हैं। पहले गांवों में इन कुंडों के पास खुले हौज भी बनाए जाते थे, जिनसे गाय, भैंस, भेड़-बकरियों, ऊंटों के लिए पेयजल की व्यवस्था होती थी।

स्वास्थ्य के लिए उत्तम है कुंड का पानी

चूरू जैसे क्षेत्र में जहां खारा भूजल अपने भीतर अनेक नुकसानदायक तत्व समेटे है तथा फिल्टर पानी की गुणवत्ता भी संदिग्ध है, कुंड में एकत्र बरसाती पालर पानी स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप है। वैद्य लीलाधर शर्मा बताते हैं कि बरसाती पालर पानी फ्लोराइड, क्लोराइड, नाईट्रेट आदि हानिकारक तत्वों से रहित होता है। जिन क्षेत्रों में भूजल में फ्लोराइड आदि नकारात्मक तत्व अधिक होते हैं, वहां के लोगों में सामान्य रूप से दांतों, हड्डियों, पाचन तंत्र के विकार देखने को मिलते हैं, वहीं कुंड का पालर पानी स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य है। स्थानीय भूजल को छोड़कर कुंड के पानी से ये समस्याएं ठीक होते हुए देखी गई हैं। भीषण गर्मी और उच्च तापमान के समय भी कुंड का भूमिगत पानी शीतल ही रहता है।

कुंड को लेकर जरूरी सावधानियां

वैद्य लीलाधर शर्मा बताते हैं कि कुंड में पानी के संग्रहण एवं उपयोग को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कुंड का पायतन या छत आदि स्थान जहां से पानी कुंड में आता है, वह एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए। पहली बरसात का पानी कुंड में भरने से टालना चाहिए क्योंकि इसमें वायुमंडल के प्रदूषक तत्व कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी आ जाते हैं। कुंड में ढक्कन वगैरह की समुचित व्यवस्था हो ताकि कोई सर्प आदि जीव उसमें प्रवेश नहीं करें तथा कूड़ा-करकट भी नहीं जाए। पानी निकालने के लिए हैंडपंप आदि की व्यवस्था होने पर पानी साफ रहेगा तथा पानी के उपयोग में सुविधा भी रहेगी।

जल संरक्षण की दिशा में अहम हैं कुंड

सामाजिक कार्यकर्ता दलीप सरावग बताते हैं कि जल की निरंतर कमी के कारण दुनिया भर के मरूस्थल इस समय अत्यधिक दबाव में हैं। जलवायु परिवर्तन और आधुनिकता की अंधी दौड़ में अत्यधिक वाहनों, एयरकंडीशर एवं अन्य मशीनों के उपयोग के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जन्म ले रही हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले निकट समय में ही हमें पेयजल के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में क्षेत्र में चल रही जल संरक्षण की परम्परा काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। हमें बूंद-बूंद पानी बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। ऐसे में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में बने कुंड यहां के लोगों की दूरगामी सोच और जल-विमर्श को लेकर उनकी समझ के परिचायक हैं ही। मरूप्रदेश में रहने वाले लोगों ने अपने जल प्रबंधन कौशल से सदियों से इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। पानी की बूंद-बूंद को सहेजना और उसका सदुपयोग करना राजस्थान वासियों की दिनचर्या का हिस्सा है। भविष्य में भी जल संरक्षण को लेकर हमारी यही सोच बरकरार रहनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ जल और जल विमर्श छोड़कर जा सकें।

प्राकृतिक सौंदर्य

जाखम बांध

प्राकृतिक सौंदर्य का विहंगम दृश्य

नवधा परदेशी
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

पक्षियों की चहचहाहट, पर्वतों का फैलाव, मानसून में बादलों की अद्वितीय छाया के बीच जाखम बांध एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। कांठल प्रदेश में घने जंगलों और इसके किनारों पर असंख्य झाड़ियों के साथ बारहमासी जाखम नदी सीतामाता अभयारण्य की प्राथमिक जीवन रेखा है। यह माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी पर जाखम बांध बना है जो प्रतापगढ़ के अनूपपूरा गांव में स्थित है।

बांध का जलग्रहण क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उप-आर्द्र से आर्द्र जलवायु की स्थिति में आता है, जिसमें जुलाई-सितम्बर के महीनों के दौरान अपेक्षाकृत उच्च आर्द्रता के साथ हल्की सर्दी और हल्की गर्मी होती है। जाखम बांध पर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में धरियावद से लगभग 30 किमी और प्रतापगढ़ शहर से लगभग 35 किमी दूर स्थित है। यह बांध क्षेत्र की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना का उद्गम है।

बांध तक जाने का मार्ग भी अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण यहां आने वाले पर्यटकों के लिए इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बना देता है। यहां मार्ग के दोनों ओर आम, सागवान, पलाश सहित अन्य वृक्ष देखे जा सकते हैं। जाखम परियोजना जनजातीय क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई का लाभ प्रदान करती है और जिले के लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाकर उनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन जाती है। जाखम परियोजना जनजाति क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। जिससे जनजाति क्षेत्र के हज़ारों कृषक लाभान्वित हुए हैं।

पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र

जाखम बांध प्राकृतिक सौन्दर्य में समृद्ध होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। मानसून के बाद जब जाखम बांध की खूबसूरती अपनी पराकाष्ठा पर होती है तब यहां सवार्धिक पर्यटक आते हैं। यह यहां आने वाले पर्यटकों को समुद्र तटीय पर्यटन स्थल जैसा दृश्य प्रस्तुत करता है। बांध के पास जाखम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस एक अनोखा दृश्य और अनुभव प्रदान करता है। विभिन्न वन्यजीवों और पक्षियों को देख पाना यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है।

इसके अलावा जिले के छोटीसादड़ी उपखंड में स्थित भंवरमाता, धरियावद उपखंड में झरनी माता स्थित झरना, केसरियावाद तालाब आदि भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

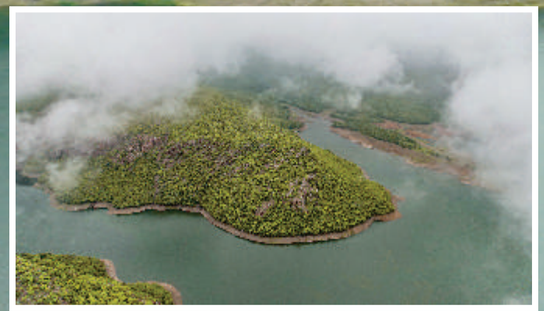

लोक जीवन में वर्षा का उल्लास

मेह सूं नेह...

चंद्रशेखर पारीक
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान के लिए वर्षा जीवन का आधार है, इसलिए यहां इसका स्वागत भी प्रतिवर्ष बिरखा बीनणी (नई-नवेली दुल्हन) की भांति लक्ष्मी मानकर किया जाता है। यहां 'मेहा तो बरसत भला' कहकर वर्षा को सदैव ही मंगलकारी माना गया है।

राजस्थान में वर्षा और मेहमान कभी-कभार ही आते, इसलिए इनके स्वागत में पलक-पांवड़े बिछाने में कोई कसर नहीं रखी जाती। लोक जीवन में जब किसी व्यक्ति का ज्यादा इंतजार होता है तो उसको बताया जाता है, 'थांनै मेह की जियां उडीक रिया हां' (आपका इंतजार वर्षा की भांति किया जा रहा है)। यहां के लोगों में वर्षा के ज्ञान और उससे जुड़ी जानकारी भी कम नहीं है। सौ कोस दूर से आने वाली हवा और 30 कोस दूर से सुनाई देती गर्जना के साथ बारिश की संभावना यहां के साधारण चरवाहे भी भली-भांति जता देते हैं।

जितनी वर्षा की लड़ी, उतनी नामों की झड़ी

बारिश के स्वागत के लिए राजस्थान में पूरा चौमासा ही मानो एक त्योहार का रूप ले लेता है। लोकगीतों से लेकर भांति-भांति के टोटके और शगुन मनाते लोगों के लिए मानसून सिर्फ अच्छी फसल या अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि इससे कहीं आगे यह पेयजल, आर्थिक उन्नति, सामाजिक संबंध और आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा है। इसीलिए राजस्थान में जितनी वर्षा की लड़ी है, उतनी ही उसके नामों की झड़ी है। यहां बारिश के छींटों से ही नामों का सिलसिला हो जाता है। पहली छांट, यानी बूंद का नाम ही हरि है। इसके बाद मेघपुहुप, बिरखा, बरखा, घणसार, मेवलियो, बूलौ, सीकर, फुंहार, छिड़को, छांटो, छांटा-छिड़को, छछोहो, टपको, टीपो, टपूकड़ो, झिरमिर, पुणंग, जीखौ, झिरमिराट, झड़ी, रीठ अर भोठ जैसे नाम मिलते हैं।

महीनों की वर्षा भी अलग-अलग

वर्षा के वेग पर भी नामों की लड़ी आगे बढ़ती है। जब 'झड़ी' लगातार बरसने लग जाए तो वह 'झड़मंडण', 'बरखावळ' या 'हलूर' कहलाती है। प्रदेश में मानसून के अलग-अलग महीनों के अनुसार वर्षा के नाम देखने को मिलते हैं। सावन की वर्षा 'लोर', भादौ की 'झड़ी', आसोज की 'मोती', कार्तिक की 'कटक', मार्गषीर्ष की 'फांसरड़ो', पौष की 'पावठ', माघ की 'मावठ', फाल्गुन की 'फटकार', चैत्र की 'चड़पड़ाट', बैसाख की 'हळोतियो', जेठ की 'झपटो' और आषाढ़ की वर्षा 'सरवांत' कहलाती है।

बूंदों के वेग पर आधारित नाम

'मेहाझड़' में जहां बूंदों की चाल और अवधि दोनों बढ़ जाती है, वहीं 'झपटै' में चाल तेज और अवधि कम होती है। इसी प्रकार त्राट, त्रम, झड़, त्राटकणों, धरहरणों भी बूंदों के न्यारे-न्यारे रूप होते हैं। मूसलाधार वर्षा की बूंदें 'छोळ' और 'आणंद' कहलाती हैं, तेज बारिश की आवाज 'सोकड़' कही जाती है। बादल और धरती को एक कर देने वाली प्रचंड बारिश की बूंदों को 'धारोळा'

की संज्ञा दी जाती है। इनके साथ होने वाली गर्जना को 'धमक या धोख' कहा जाता है। साथ ही, बहती प्रचंड पवन 'खरस', 'बावळ' या 'सूंटो' कहलाती है। जिस रात जमकर बारिश होती है, उसे 'महारैण' कहा जाता है। सुबह की वर्षा को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि पिछले प्रहर की बारिश भली मानी जाती है। वर्षा बरसने की प्रक्रिया 'बूंठणूं' और इसकी समाप्ति 'उबरेलो' कहलाती है। वर्षा के जल को 'पालर पाणी' कहा जाता है।

बादलों के नामों का भंडार

मरुधरा में वर्षा सबसे कम बरसती है लेकिन इसकी आवभगत के लिए पूरा चौमासा अर्थात चार मास रखे गए हैं। यहां पर लोक शब्दावली में वर्षा के लिए तो अनेक नाम मिलते ही हैं लेकिन उसे लेकर आने वाले बादलों के भी सैकड़ों नाम मिल जाते हैं। यहां जितने बादलों के नाम हैं, उतने तो बादल भी नहीं होते होंगे। बादलों को राजस्थानी भाषा में जळधर, जळहर, जळवाह, जळधरण, जळद, जीभूत, घटा, घर, सारंग, बोम, बोमचर, मेघ, मेघाडंबर, मुदिर, महिमंडण, धरमंडण, भरणनद, पाथोद, पीथळ, पिरथीराज, पिरथीपाळ, पावस, डाबर, डंबर, दळबादळ, घण, घणमंड, जळजाळ, काळी, कांठळ, कळायण, कारायण, कंद, हब्र, मैंमट, मेहाजळ, मेघांण, महाघंण, रामइयो, सेहर, बसु, बैकुंठवासी, महीरंजण, अंब, इलम, नभराट, ध्रवण, पिंगळ, धाराधर, जगजीवण, जळबाहण, अभ्र, बरसण, नीरद, पाळग, बळाहक, जळवह, जळमंडळ, घणांघण, तड़ितवांन, तोईद, परजन, आकासी, जळमुक, जळमंड, महिपाळ, तरत्र, निरझर, भरणनिवांण, तनयतू, गयणी, महत, किलांण, रौरगंजण जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता रहा है। इन नामों के अलावा स्थानीयता और बोली के आधार पर कुछ और नाम जुड़ जाएं तो अचंभे की बात नहीं होगी।

आकार-प्रकार पर भी बदलते नाम

राजस्थान के साहित्य और संस्कृति में बादलों के आकार-प्रकार, बनावट, चाल और रफ्तार के अलावा निकटता और दूरी के आधार पर भी उनका नामकरण होता रहा है। वर्षा के बड़े बादलों का नाम 'सिखर' तो छोटे-छोटे लहरदार बादल 'छीतरी' कहलाते हैं। बादलों के झुंड से अलग रहा छोटा-सा बादल भी 'चूंखो या चूंखलो' पुकारा जाता है। मस्त पवन पर बरसने को तैयार दूर से आते बादल 'कळायण' कहलाते हैं। काले बादलों की घटाटोप सेना के आगे ध्वजा की भांति चलते सफेद बादल 'कोरण' या 'कागोलड़' कहे जाते हैं। सफेद बादलों के ठीक पीछे उमड़ती-घुमड़ती भूरी-काली घटा 'कांठळ' कही जाती हैं।

आत्मीय संबंध...'मेहा तो बरसत भला'

राजस्थान में बादलों के नामकरण में उनकी ऊंचाई-निचाई और स्थिति का भी महत्व है। पतले और ऊंचे बादल 'कस या कसवाड़' कहे जाते हैं, नैऋत्य से ईशान की ओर जरा अलग हटकर बहते बादलों को 'ऊंब' की संज्ञा दी जाती है। घटाओं का जमावड़ा 'घटाटोप' कहा जाता है। जरा-जरा सी बरसती घटाएं 'सहाड़' कहलाती हैं, पश्चिम की ओर से पवन के वेग के साथ दौड़ती घटाएं 'लोर' कहलाती हैं। बरस चुके बादल 'रींछी' कहलाते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान और बारिश का संबंध अत्यंत आत्मीय है और अनूठा भी।

मौसम विभाग की अनूठी पहल

कृषकों की राह को सुगम बना रही 'पंचायत मौसम सेवा'

सुधाकर सोनी
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, जो सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। देश की लगभग 47 प्रतिशत आबादी के लिए खेती आजीविका का साधन है और करीब 70 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ी हुई है। यद्यपि वर्तमान समय में कृषक खेती की नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं मगर फिर भी किसी न किसी रूप में हमारी कृषि आज भी मौसम पर बहुत अधिक निर्भर है।

मौसम की अनिश्चितता किसानों के लिए अक्सर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अचानक अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाला पड़ने जैसी वजहों से किसान की फसल चौपट हो जाती है। कृषि उत्पादन कम होने से खाद्यान्न आपूर्ति में भी बाधा आती है जिससे कीमतों में वृद्धि होती है जो अंततः खाद्य महंगाई को बढ़ावा देती है। ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी किसान के साथ ही आम उपभोक्ता के लिए भी बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यदि कृषक को प्रति दिन उसके क्षेत्र के मौसम की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती रहे तो वह काफी हद तक अपनी फसल खराब होने से बचा सकता है।

कृषकों की इस तकलीफ को समझते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 15 जनवरी 2024 को अपने स्थापना दिवस पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता, खास तौर से किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की है। विभाग ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पंचायतीराज मंत्रालय तथा ग्रीन अलर्ट वेब पोर्टल के सहयोग से पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर पंचायत स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान जारी करना शुरू किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा के अनुसार 'पंचायत मौसम सेवा' का उद्देश्य देश भर के हर गांव में अधिक से अधिक किसानों से जुड़ना और उन्हें गंभीर मौसम की चेतावनी देने के अलावा उनके क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और हवा की गति तथा क्लाउड कवरेज जैसे सभी मौसम मापदंडों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। फिलहाल इस सेवा के अंतर्गत अगले कुछ घंटों से लेकर आगामी पांच दिनों का मौसम पूर्वानुमान और साप्ताहिक मौसम आउटलुक उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच मौसम संबंधी टिप्पणियों और पूर्वानुमानों को अपडेट किया जाता है। किसानों को इस सेवा का अधिक से अधिक लाभ मिले, इस हेतु मौसम विभाग ग्राम पंचायतों के सचिवों, सरपंचों और वार्ड सदस्यों को इस अभियान से जोड़ रहा है जो अपने क्षेत्र के किसानों को इस सेवा की विस्तृत जानकारी देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं।

इस तरह मिलेगी मौसम की जानकारी

मौसम संबंधी पूर्वानुमान जानने के लिए सबसे पहले यूजर को www-greenalerts-in वेब पोर्टल पर जाकर अपना राज्य चुनना होगा। फिर उस राज्य के जिलों की सूची में से संबंधित जिले के टैब पर क्लिक करने पर उसके सामने जिले के सभी ब्लॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। वांछित ब्लॉक वाले टैब पर क्लिक करने पर यूजर अपनी ग्राम पंचायत सहित उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों का समेकित मौसम पूर्वानुमान देख सकेगा।

'मौसम' एप पर भी उपलब्ध होगी जानकारी

ग्रीन अलर्ट वेब पोर्टल के अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग के मोबाइल ऐप 'मौसम' के माध्यम से भी किसान और आमजन मौसम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप पर किसानों को सिर्फ स्थान का नाम लिखना होगा या क्षेत्र का पिनकोड डालना होगा। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर उसके क्षेत्र के मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, हवा गति को कवर किया जाएगा। साथ ही गंभीर मौसम के लिए अलर्ट भी जारी होगा। अब तक देश भर के सभी जिलों और 1,200 शहरों और कस्बों के लिए सभी प्रकार के गंभीर मौसम के लिए नाउकास्ट कर दिया गया है।

क्षेत्रीय भाषाओं में भी मौसम का हाल

पंचायत मौसम सेवा कि ये खास बात है कि इसमें मौसम की जानकारी दस से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है जिनमें हिंदी और इंग्लिश के अलावा तेलगु, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू जैसी क्षेत्रीय भाषाएं भी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर भी राजस्थानवासियों को दी जा रही अपनी नियमित सेवाओं के लिए एक ऐप विकसित कर रहा है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस एप के माध्यम से केंद्र द्वारा खास तौर से राजस्थान से संबंधित प्रतिदिन दी जा रही सेवाओं जैसे मौसम बुलेटिंस, कृषि संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी सहित कई जानकारियां तुरंत मिल सकेगी।

शामिल हैं। इससे विभिन्न प्रान्तों के किसानों को अपनी स्थानीय भाषा में मौसम संबंधी जानकारी मिल पा रही है और वे सुगमता से उसे समझ पा रहे हैं।

पंचायत मौसम सेवा के लाभ

मौसम विज्ञान विभाग के इस प्रयास से कृषकों, पशुपालकों तथा ग्रामीणों को कई फायदे हैं। किसान मौसम खराब होने से पहले से अपनी उपज को सुरक्षित जगह पर स्टोर कर सकता है । बारिश कम होगी या ज्यादा, इसकी जानकारी प्राप्त कर सिंचाई का बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्लाउड कवरेज से बादलों की स्थिति जानी जा सकती है। यदि आसमान साफ़ है तो कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है, क्योंकि फसल पर कीटनाशक का असर रहने के लिए जरूरी है कि छिड़काव के बाद चार-पांच दिन तक बारिश न हो। पशुपालक बारिश और बिजली गिरने के बारे में पूर्वानुमान प्राप्त होने पर अपने पशुओं को सुरक्षित और शैड वाले स्थान पर ले जा सकता है। आमजन भी हवा की गति और दिशा के बारे में जानकार तूफ़ान, चक्रवात आदि से बच सकते हैं।

मौसम के हाल के साथ कृषि सलाह भी

पंचायत मौसम सेवा कृषकों के लिए 'आम के आम गुठलियों के दाम' वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। उन्हें इसके माध्यम से मौसम का सटीक पूर्वानुमान तो मिल ही रहा है साथ ही मौसम पूर्वानुमान वाले पेज पर एक अन्य सेक्शन 'कृषि सलाह' के माध्यम से तत्कालीन मौसम की प्रमुख फसलों के बारे में उपयोगी सुझाव भी दिए जा रहे हैं। उदहारण के लिए शीत ऋतु में रबी की प्रमुख फसलों (जैसे गेहूं, सरसों, मक्का और चना) को रोग और कीट से बचाने तथा सिंचाई प्रबंधन की जानकारी मिलेगी तो ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसलों की देखभाल के बारे में महत्त्वपूर्ण टिप्स उपलब्ध होंगे।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा शुरू की गई पंचायत मौसम सेवा कृषक हित में उल्लेखनीय कदम है। इस सेवा का लाभ उठाकर किसान न केवल कृषि संबंधी जोखिम कम कर सकता है, बल्कि अपनी आय में भी वृद्धि कर सकता है। एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार यदि वर्षा आधारित क्षेत्रों में एक छोटा किसान मौसम पूर्वानुमान का उपयोग करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसे सालाना हजारों रुपये का लाभ होता है। देश के सभी किसानों तक इस सेवा की पहुंच हो जाए तो जीडीपी को तो भारी फायदा होगा ही, केंद्र सरकार के किसानों की आय दुगुनी करने के संकल्प को भी बल मिलेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने मौसम संबंधी कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सिस्टम के तहत कैप सचेत नामक सेवा शुरू की है जिसमें उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से मौसम संबंधी चेतावनी भेजी जाती है। राजस्थान में यह कार्य राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के संयुक्त सहयोग के किया जा रहा है।

श्री शर्मा ने बताया कि इस सेवा के तहत किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश, आंधी- तूफान, हीट वेव या मौसम संबंधी गंभीर आपदा जनित चेतावनी जियो टैगिंग सिस्टम की मदद से उस संबंधित क्षेत्र में एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों पर कुछ ही मिनट में एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त एनडीएमए के कैप सचेत (CAP SACHET) नामक एप पर उपभोक्ता मौसम संबंधी कम गंभीर सभी छोटे बड़े अलर्ट भी जान सकता है।

30 वर्ष बाद शेखावाटी की उम्मीदों को मिले पंख

1994 में हुआ था समझौता; हरियाणा के ताजेवाला हैड से सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं नीमकाथाना को मिलेगा यमुना का पानी

राकेश कुमार ढाका
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के भगीरथी प्रयासों से अब शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं नीमकाथाना जिले को यमुना का पानी मिलने का सपना पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, तत्कालीन जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में नई दिल्ली में 17 फरवरी 2024 को एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए इस एमओयू के तहत ताजेवाला हैड की संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी थी। इस योजना के मूर्त रूप लेने के बाद राजस्थान को ताजेवाला हैड से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा और बारिश में व्यर्थ बह जाने वाले जल का भी समुचित उपयोग हो सकेगा। प्रोजेक्ट में चार भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएंगी जिनमें से तीन पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का पानी राज्य के तीन जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं नीमकाथाना को उपलब्ध कराया जायेगा और चौथी पाइपलाइन के द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी भिवानी दादरी और हिसार के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। समझौते के दौरान प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण यह योजना काफी समय से लंबित थी। इसके धरातल पर उतरने के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं नीमकाथाना की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा।

यमुना जल पर मई 1994 के समझौते अनुसार अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा हरियाणा स्थित ताजेवाला हैड पर मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) में 1917 क्यूसेक या वार्षिक 577 एम.सी.एम जल राजस्थान को आवंटित किया गया था। वर्तमान में ताजेवाला हैड से राजस्थान को जल लाने के लिए कैरियर सिस्टम उपलब्ध नहीं है। राज्य द्वारा वर्ष 2003 में हरियाणा की नहरों को रिमॉडलिंग कर राजस्थान में उक्त जल लाए जाने के लिए पुन: वर्ष 2017 में भूमिगत प्रवाह प्रणाली के माध्यम से जल लाने हेतु हरियाणा सरकार को एमओयू भेजा गया जिस पर हरियाणा राज्य की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी थी। पिछले 30 वर्षों के दौरान राजस्थान द्वारा लगातार इस मुद्दे को अपर यमुना रिव्यू कमेटी व अन्य अंतराज्यीय बैठकों में निरंतर रखा गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रयासों से नई दिल्ली में हुए त्रिपक्षीय एमओयू के तहत प्रथम चरण में पेयजल के लिए ताजेवाला हैड से जल को राजस्थान लाने के कैरियर सिस्टम के लिए संयुक्त डीपीआर 4 माह में बनाने पर सहमति बनी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किये प्रारम्भिक आंकलन अनुसार प्रथम चरण में राजस्थान को 3200/3300 एम.एम डाईमीटर के तीन पाइपों द्वारा जुलाई से अक्टूबर में यमुना जल दिया जाना प्रस्तावित किया गया, जिसकी अनुमानित लागत रुपये 19,136 करोड़ आंकी गई।

केंद्र, राज्य व हरियाणा सरकार के बीच शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए हुए एमओयू के तहत बारिश के सीजन में राजस्थान को यमुना नदी के बाढ़ का व्यर्थ बहने वाला पानी ताजेवाला हैड वर्क्स से सप्लाई करवाया जाएगा। ताजेवाला हैड वर्क्स परियोजना के तहत शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए सिंचाई विभाग के सीकर डिविजन कार्यालय को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्ययोजना के अनुसार शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनूं व नीमकाथाना जिले में जरूरत वाले गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए हांसियावास राजगढ़ से अलग-अलग तीन पाइप लाइन निकाली जाएगी। इसमें एक पाइप लाइन चूरू के लिए व एक-एक पाइप लाइन झुंझुनूं व सीकर निकाली जाएगी। जहां से तीनों जिलों में पानी की सप्लाई होगी। ताजेवाला हैडवर्क्स (हथिनीकुंड बैराज) से चूरू के हांसियावास (राजगढ़) तक यमुना का पानी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट की संभावित लागत 19,136 करोड़ रुपये के करीब मानी गई है। इसके लिए लगभग 263 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद पानी को सीकर, नीमकाथाना, झुंझुनूं व चूरू जिले में जरूरत के अनुसार सप्लाई किया जाएगा। परियोजना के तहत चूरू एवं झुंझुनूं में वाटर रिजर्ववायर तैयार किए जाएंगे। ईआरसीपी तथा ताजेवाला हैड वर्क्स परियोजना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक हैं, ऐसे में इनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाकर आगामी चार माह में ताजेवाला हैड वर्क्स परियोजना की डीपीआर तैयार की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
21 जून, 2024 के अवसर पर
श्रीनगर में डल झील के किनारे योग मुद्रा में।

10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

इंटरनेशनल योग दिवस मनाने का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम ने यूएन में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान 177 देश भारत के समर्थन में आए थे। इसके बाद साल 2015 की 21 जून को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम **योग फॉर सेल्फ एण्ड सोसायटी** है। 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत एवं योगाभ्यास करते राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं अन्य।

भारतीय संस्कृति की विश्व को अमूल्य देन

भारत के सभी धर्मों में आदिकाल से रहा है योग का महत्व

हरिओम सिंह गुर्जर
संयुक्त निदेशक

योग भारतीय संस्कृति की विश्व को अमूल्य देन है। इसके द्वारा शरीर एवं मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ्य रखने के साथ अनेक व्याधियों से बचा जा सकता है। योग आदिकाल से भारत में प्रचलित रहा है, इसे जन-जन तक पहुंचाने तथा इसकी दैनिक जीवन में महत्ता को वर्तमान में देश की सीमाओं से बाहर पहुंचाने में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस का विशेष योगदान रहा है। योग क्रियाएं सूर्य पर आधारित होने तथा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने के कारण 21 जून को योग दिवस की महत्ता बढ जाती है। भारत की सांस्कृतिक विरासत योग को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए 27 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व समुदाय से आह्वान किया था। 11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 सह-समर्थक देशों के साथ 21 जून को "अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस" मनाने का संकल्प सर्व सम्मति से अनुमोदित किया।

प्रथम अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस

प्रथम अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 का राजपथ नई दिल्ली में सफल आयोजन किया गया। इसमें दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड बने, प्रथम 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग सत्र तथा दूसरा अभ्यास सत्र में 84 देशों के नागरिकों की प्रतिभागिता का होना। इसी श्रृंखला में "सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग" विषय पर दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई जिसमें भारत तथा विदेश से लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

योग का संक्षिप्त इतिहास

श्रुति परम्परा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदिगुरु या आदि योगी हैं। हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदियोगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। इन सप्त ऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग-अलग भागों में प्रसारित किया।

योग का व्यापक स्वरूप तथा उसका परिणाम सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी सभ्यताओं 2700 ई.पू.-की अमर संस्कृति का प्रतिफल माना जाता है। सिंधु, सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती अनेक आकृतियों के साथ प्राप्त ढेरों मुहरें एवं जीवाश्म अवशेष इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था। वैदिक एवं उपनिषद परम्परा, शैव, वैष्णव तथा तांत्रिक परम्परा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं श्रीमद् भगवत गीता समेत महाभारत जैसे महाकाव्यों, बौद्ध एवं जैन परम्परा के साथ-साथ विश्व की लोक विरासत में भी योग मिलता है। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और उनके निहितार्थ और इससे संबंधित ज्ञान को पांतजलि योग सूत्र नामक ग्रन्थ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया।

सनातन धर्म में योग दर्शन

योग शब्द का अर्थ समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की पांच अवस्थाएं हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरूद्धावस्था। चित्त की एकाग्र अवस्था में योग का प्रारम्भ होता है। योग की प्रमुख चार पद्धतियां सनातन धर्म में प्रचलित रही हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एवं राजयोग। अर्थवेद एवं गौरखवानी में अष्टचक्रों का वर्णन किया गया है। गीता में भगवान

श्रीकृष्ण द्वारा कर्म योग एवं ज्ञान योग के बारे में संदेश दिया है। योगदर्शन में अत्यंत उच्च कोटि के योगियों के लिए कैवल्य योग का विधान किया गया है। इसी प्रकार हठयोग में 'ह' का अर्थ सूर्य अर्थात पिंगला नाडी एवं 'ठ' का अर्थ चन्द्र अर्थात सुषुम्ना नाडी या स्वरों का मिलन से है।

महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों को पांच भागों में विभक्त किया है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन पांचों प्रकार की क्लिष्टि और अक्लिष्ट वृत्तियों को रोक देना ही योग है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, प्रमाणिक व वैज्ञानिक माना जाता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि प्रमुख हैं।

नाथ सम्प्रदाय के गुरु गोरखनाथ रचित हिन्दी और संस्कृत की अनेक पुस्तकों में हठयोग के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। स्वामी विवेकानन्द का भक्ति योग, महर्षि अरविन्द के दर्शन में सम्पूर्ण जीवन योग है और सम्पूर्ण मानवीय क्रियाएं योग है। इनके द्वारा आध्यात्मिक विकासवाद का सिद्धान्त दिया गया है। इसी कड़ी में स्वामी कुवलयानन्द, स्वामी शिवानन्द, वीके एस आयंगर जैसे योग ऋषियों द्वारा भारतीय योग पद्धति को अन्तरराष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का कार्य किया जाता रहा है। वर्तमान में स्वामी रामदेव द्वारा पतंजलि योगपीठ के माध्यम से भारतीय जनमानस तक योग के महत्व को साकार किया जा रहा है।

बौद्ध योग दर्शन

भारतीय योग विद्याओं में बौद्ध परम्परा का भी अति विशिष्ट स्थान रहा है। ध्यान बौद्ध साधना का हृदय है। बौद्ध परम्परा के अनुसार अकुशल चित्त के कारण ही साधक को संसार भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए चित्त को स्थिर करने के लिये ही ध्यान की आवश्यकता है। अर्थात किसी एक पवित्र विषय पर चित्त स्थिर करना ही ध्यान है।

भगवान बुद्ध का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है। इसमें साधक का लक्ष्य अर्हत् पद या बोधिसत्व की प्राप्ति है। बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्ति के लिए शील विशुद्धि एवं चित्त विशुद्धि का उल्लेख किया है। सुतपिटक के अनेक सूत्रों में बुद्ध ने समाधि की शिक्षा दी है। आचार्य बुद्ध घोष का 'विशुद्धिमग्ग' चित्त विशुद्धि विषय का सबसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ माना जाता है। बौद्ध योग की भारत में प्रचलित ध्यान प्रणाली विपश्यना है। विपश्यना के लिए तीन शर्तें हैं जिनमें अनित्य का ज्ञान, दुखः का ज्ञान, और अनात्म का ज्ञान होने पर ही विपश्यना प्रगट होती है। विपश्यना में मौन का कड़ाई से पालन कराया जाता है, वर्तमान में आनापान सती और काय विपश्यना दो पद्धति भारत में प्रचलित है।

जैन योग दर्शन

जैन योग 'जिन' दर्शन पर आधारित है जिसमें जीवन का अन्तिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। 'जिन' का शाब्दिक अर्थ है-विजेता अर्थात् आत्म-विजेता। राग-द्वेष को जीत कर अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाले जिन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी जाति या वर्ण का हो अपने आपको साधना द्वारा 'जिन' की स्थिति तक विकसित कर सकता है। जैन योग के आदि प्रणेता प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे।

भगवान महावीर के सैकड़ों शिष्य केवलज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्यय ज्ञानी थे। जैन योग में चार युग देखने को मिलते हैं ध्यान योग, शास्त्रीय ज्ञान और मंत्र योग, उसके बाद तंत्र, मंत्र एवं हठ योग तथा उसके बाद प्रेक्षाध्यान योग का अभ्युदय हुआ। प्रेक्षाध्यान में कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, शरीर लेक्षा, चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा और लेश्या ध्यान प्रमुख योग पद्धतियां हैं।

आर्चाय श्रमाश्रमण ने वि.सं. छठी शताब्दी में ध्यानशतक् की रचना की, आचार्य कुन्दकुन्द, जिन भद्रगणि श्रमाश्रमण और पूज्यपाद के ग्रन्थों में ध्यान की मौलिक पद्धति सुरक्षित है। आचार्य हरिभद्र ने विक्रम आठवीं शताब्दी में महर्षि पतंजलि के योगदर्शन की पद्धति को जैन साधना पद्धति के साथ जोड़ा। 'नमस्कार महामंत्र कल्प', 'पद्मावती कल्प', 'भैरव कल्प', 'शत्रु जय कल्प' आदि अनेक कल्पों एवं जप विधियों का निर्माण हुआ। शुभचन्द ने 'ज्ञानार्णव' और आचार्य हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र' की रचना की। आचार्य रत्नशेखर ने गुणस्थान क्रमारोह लिखा।

विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी में जयाचार्य ने ध्यान का गहरा अभ्यास किया था। उनकी देशी भाषा में दो महत्वपूर्ण कृतियां मिलती हैं-बड़ों ध्यान और छोटो ध्यान। विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आचार्य श्री तुलसी ने विलुप्त जैन योग परम्परा को पुनर्जीवित कर संस्कृत की सूत्रात्मक शैली में 'मनोनुशासनमृ' नामक ग्रन्थ लिखा।

इस प्रकार भारतीय दर्शन में योग का महत्व आदिकाल से रहा है तथा सनातन, जैन, बौद्ध परम्पराओं द्वारा इसे उत्कृष्टता प्रदान की जाती रही है। सिख धर्मगुरुओं द्वारा भी योग के महत्व को अनेक रूपों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का कार्य अनवरत किया जाता रहा है।

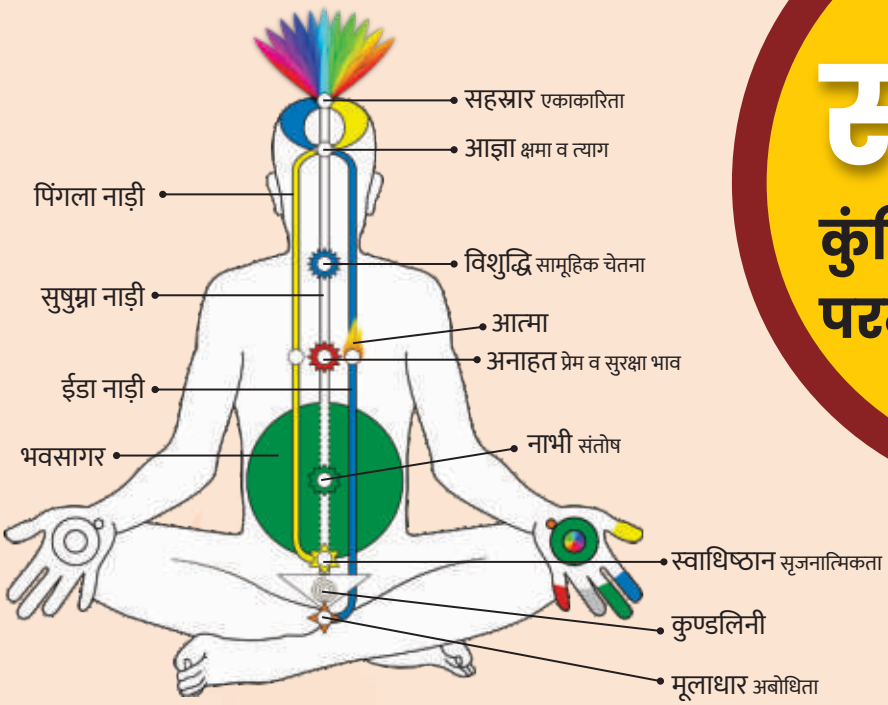

सहज योग

कुंडिलिनी शक्ति का परमशक्ति से जुड़ाव

डॉ. वीरेन्द्र सिंह
वित्तीय सलाहकार, सूजस

योग की अवधारणा हमारे देश में आदिकाल से ही है। महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में योग के आठ अंग वर्णित हैं यथा-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। साधारण बोलचाल भाषा में योग शब्द का प्रयोग जोड़ने (Plus) से लगाया जाता है। अपने अन्दर बसी हुई कुण्डलिनी शक्ति को चारों तरफ फैली हुई सर्वव्यापी परमशक्ति से जोड़ना ही योग है। हम सभी के अन्दर इस सर्वव्यापी परमशक्ति से जुड़ने की व्यवस्था जन्म से ही मौजूद होती है। जिसे उक्त सूक्ष्म शरीर की आकृति से समझा जा सकता है।

प्रत्येक मनुष्य के अन्दर तीन नाड़ियां एवं सात मुख्य उर्जा केंद्र हैं जिन्हें "चक्र" कहा जाता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित त्रिकोणाकार अस्थि (Sacrum Bone) में कुण्डलिनी नामक शक्ति सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है।

सहज योग ध्यान की प्रक्रिया द्वारा जब कुण्डलिनी शक्ति को जागृत कर, चारों ओर फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से एकाकार किया जाता है तो यहीं योग है और इसकी अनुभूति हमें अपने स्थूल शरीर पर ठण्डी-ठण्डी चैतन्य लहरियों के रूप में होने लगती है और हमारा शरीर एवं मन बिना किसी औषधि के रोग मुक्त होने लगता है।

आज से लगभग चौदह हजार वर्ष पहले मार्कण्डेय मुनि ने कुण्डलिनी शक्ति के जागरण का उल्लेख किया था। श्री राम जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में विद्या अर्जन करने गये थे तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें इसी कुण्डलिनी शक्ति के जागरण का ज्ञान दिया था। हिन्दु धर्म के प्रवर्तक आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे "स्पंद" कहा, जीजस क्राइस्ट ने इसे "All Prevailing Power of Divine Love" कहा, पैगम्बर मुहम्मद साहब ने इसे "रूह" कहा, संत कबीर ने इसे "श्रुति" कहा तथा गुरू नानक साहब ने इसे "अलख निरंजन" कहा अर्थात इसका वर्णन सभी धर्मों में किया गया।

कुण्डलिनी शक्ति के जागरण की क्रिया एक जीवन्त क्रिया है तथा इस घटना को घटित होने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने भी जीवन्त कार्य होते हैं, वह स्वत: होते हैं जैसे-बीजों में अंकुर निकलना, फूलों का फल बनना आदि। अपनी कुण्डलिनी शक्ति के जागरण के लिए हमारे अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए तथा हमें अपने सूक्ष्म शरीर में संतुलन स्थापित करना आना चाहिए। संतुलन स्थापित करने के लिए हमें अपने अंदर स्थित सूक्ष्म नाड़ियों पर जाना होगा, ताकि कुण्डलिनी मां हमारी मध्य नाड़ी से होते हुए हमारे सहस्रार चक्र को भेदन करते हुए चारों ओर फैली हुई शक्ति से जुड़ सकें।

1. **बायीं नाड़ी या ईडा नाड़ी या चन्द्र नाड़ी (आकृति में नीले रंग से दर्शायी गयी है)** - इस नाड़ी से हमारी इच्छाएं, भावनाएं तथा समस्त भूतकाल के विचार नियंत्रित होते हैं।
2. **दायीं नाड़ी या पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी (आकृति में पीले रंग से दर्शायी गयी है)** - इस नाड़ी से हमारी क्रिया शक्ति, अहंकार तथा समस्त भविष्यकाल के विचार नियंत्रित होते हैं।
3. **मध्य नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी या ब्रह्म नाड़ी (आकृति में सफेद रंग से दर्शायी गयी है)** - इस नाड़ी से हमारे अन्दर संतुलन, वर्तमान, निर्विचारिता तथा परमशक्ति से एकाकारिता स्थापित होती है।

जब हम ध्यान में बैठतें है तो हमारे अन्दर विचारों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। एक दृष्टा की भांति स्वयं को देखना है। हमें देखना है, कि आने वाले विचार भूतकाल के हैं अथवा भविष्यकाल के। यदि विचार भूतकाल के हैं तो हमें अपनी बायीं नाड़ी को शुद्ध करना होगा। यदि विचार भविष्यकाल के हैं तो हमें दायीं नाड़ी को शुद्ध करना होगा। मध्य नाड़ी में कोई विचार नहीं होते। जब हम मध्य नाड़ी में आते हैं तो हम निर्विचारिता में जाकर परमशक्ति से एकाकार होने लगते हैं।

नाड़ी शुद्धिकरण

बायीं नाड़ी को शुद्ध करना

अपना बायां हाथ गोद में रखना है तथा दाहिना हाथ भूमि मां पर रखना है और प्रार्थना करनी है, मां, कृपया हमारे शरीर के बायें हिस्से के समस्त रोग, दोष एवं भूतकाल के विचारों को भूमि मां में निकाल दीजिए। जब हम "मां" शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर स्थित कुण्डलिनी शक्ति, जो मां स्वरूप है, उसमें कम्पन होने लगता है। यह प्रार्थना दो-तीन बार करने पर हम देखेंगे कि हमारे भूतकाल के विचार जो निरन्तर चल रहे थे उनमें ठहराव आने लग गया है।

दायीं नाड़ी को शुद्ध करना

अपना दाहिना हाथ गोद में रखना है तथा बायां हाथ कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर करना है, और प्रार्थना करनी है, मां, कृपया हमारे शरीर के दाहिने हिस्से के समस्त रोग, दोष एवं भविष्य के विचारों को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। यह प्रार्थना दो-तीन बार करने पर हम देखेंगे कि हमारे भविष्य के विचार एवं चिंताए रूक गयी हैं।

मध्य नाड़ी में स्थापित होना

अपने दोनों हाथों को घुटने पर रख लेंगे तथा प्रार्थना करेंगे, कुण्डलिनी मां, कृपया हमारे शरीर में संतुलन स्थापित कर दीजिए। कुण्डलिनी मां कृपया हमें निर्विचारिता में स्थापित कर दीजिए। कुण्डलिनी मां कृपया हमारी कुण्डलिनी शक्ति जागृत कर दीजिए।

यह प्रार्थना लगातार करने पर हम देखेंगे, कि हमारे अन्दर कोई विचार नहीं है। जैसे ही हम निर्विचारिता में जाने लगेंगे, हमारे अन्दर की कुण्डलिनी शक्ति स्वतः जागृत होकर मध्य नाड़ी से उठकर हमारे सिर के अन्दर स्थित तालू भाग को छेदती हुई चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करेंगी और हमें अपने हाथ की हथेलियों में, अगुंलियों के पोरों पर तथा सिर के तालू भाग पर ठण्डी-ठण्डी चैतन्य लहरियों की अनुभूति होने लगेगी। यहीं हमारी योग अवस्था है। इसी अवस्था में हम आत्मस्वरूप बन जाते हैं। हम विश्वव्यापी बन जाते है और कहते हैं-

"अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।"

अर्थात - जिनका हृदय बड़ा होता है, उनके लिए पूरी धरती ही परिवार होती है जिनका हृदय छोटा होता है उनकी सोच, यह अपना है, वह पराया है, की होती है।

सर्व हित काजे, राम द्वारे ...

22 जनवरी, 2024 को भगवान राम के बालरूप विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, 11 मार्च को अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों के साथ पहली बार अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश-प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

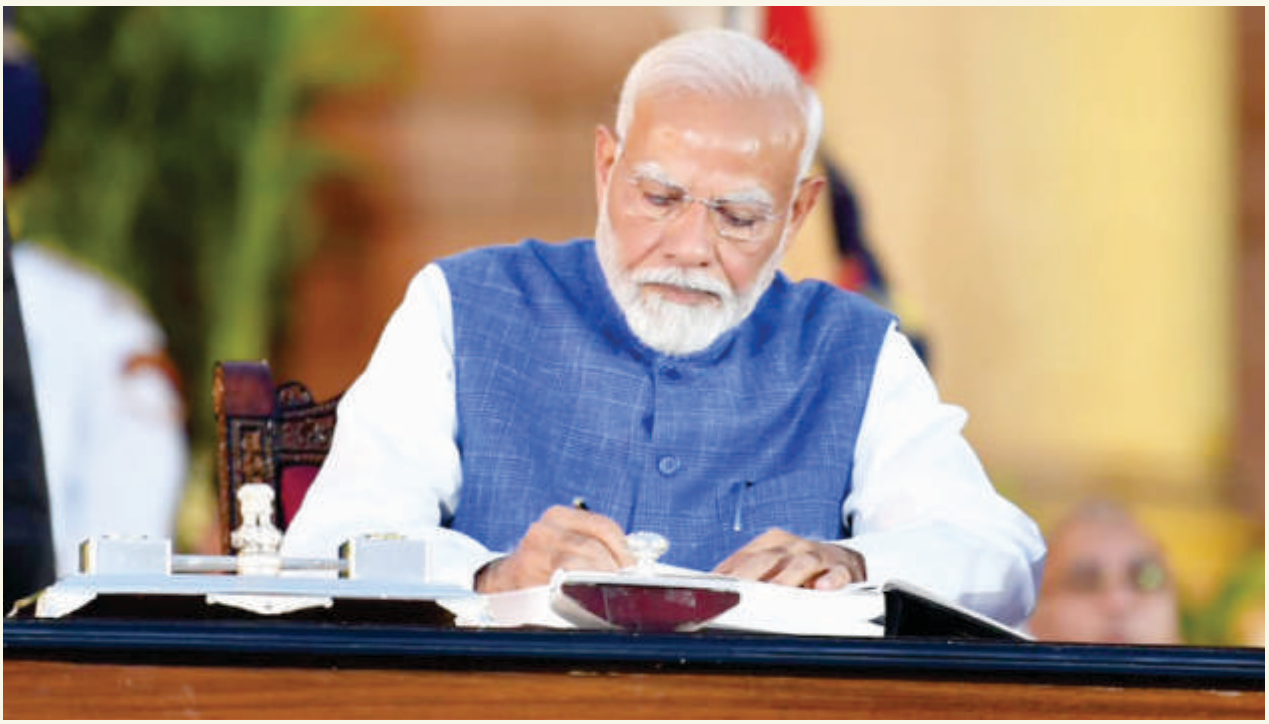

... हस्ताक्षर नवयुग निरन्तर ... | 3.0

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2081
रविवार, 9 जून, 2024

"मैं 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने तथा देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मंत्रिपरिषद के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"

'राष्ट्र प्रथम' लक्ष्य के साथ विकसित भारत की शपथ

देश को वर्षों से कुशल नेतृत्व प्रदान कर विकास पथ पर त्वरित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने 9 जून, 2024 को भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार एक बार पुन: दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

श्री मोदी वर्ष 1962 के बाद ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। श्री मोदी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों एवं विविध क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु ने यह शपथ दिलाई। उनके साथ 71 मंत्रिपरिषद सदस्यों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

श्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा, "हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 के इरादे के साथ 'राष्ट्र प्रथम' के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे" साथ ही "हमें देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसे किसी और देश ने कभी हासिल नहीं किया" उन्होंने कहा "हमारी टीम के लिए न तो समय का बंधन है, न सोचने की सीमाएं और न ही पुरुषार्थ के लिए कोई तय मानदण्ड"। इन्ही लक्ष्यों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला निर्णय देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए करते हुए पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त की फाइल पर हस्ताक्षर किए।

मैं नरेन्द्र दामोदरदास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ...

कैबिनेट मंत्री

श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्रालय

श्री अमित शाह
गृह मंत्रालय
सहकारिता मंत्रालय

श्री नितिन जयराम गडकरी
सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय

श्री जगत प्रकाश नड्डा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

श्री शिवराज सिंह चौहान
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्रीमती निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर
विदेश मंत्रालय

श्री मनोहर लाल
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
बिजली मंत्रालय

श्री एच. डी. कुमारस्वामी
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक
उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय

श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री धर्मेन्द्र प्रधान
शिक्षा मंत्रालय

श्री जीतन राम मांझी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्री राजीव रंजन सिंह
उर्फ ललन सिंह
पंचायती राज मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय

श्री सर्बानंद सोनोवाल
पत्तन, पोत परिवहन और
जलमार्ग मंत्रालय

डॉ. वीरेंद्र कुमार
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय

श्री किंजरापु राममोहन नायडू
नागरिक विमानन मंत्रालय

श्री प्रल्हाद जोशी
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

श्री जुएल ओराम
जनजातीय कार्य मंत्रालय

श्री गिरिराज सिंह
कपड़ा मंत्रालय

श्री अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

कैबिनेट मंत्री

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
संचार मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

श्री भूपेंद्र यादव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
संस्कृति मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

श्री किरण रिजिजू
संसदीय कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

श्री हरदीप सिंह पुरी
पेट्रोलियम एवं प्रकृति
गैस मंत्रालय

श्री मनसुख एल. मंडाविया
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

श्री जी किशन रेड्डी
कोयला मंत्रालय
खान मंत्रालय

श्री चिराग पासवान
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

श्री सी. आर. पाटिल
जल शक्ति मंत्रालय

पड़ोस प्रथम नीति

शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित पड़ोसी देशों के प्रतिनिधि - बायें से श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' (प्रधानमंत्री नेपाल), श्रीमती शेख हसीना (प्रधानमंत्री बांग्लादेश), श्री मोहम्मद मुइज्ज़ू (राष्ट्रपति मालदीव), श्री जगदीप धनखड़ (उपराष्ट्रपति भारत), श्रीमती द्रौपदी मुर्मु (राष्ट्रपति भारत), श्री नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री भारत), श्री रानिल विक्रमसिंघे (राष्ट्रपति श्रीलंका), श्री अहमद अफीफ (उपराष्ट्रपति सेशल्स), श्री प्रविंद जगन्नाथ (प्रधानमंत्री मॉरीशस), श्री शेरिंग टोबगे (प्रधानमंत्री भूटान)

राज्य मंत्री

श्री राव इन्द्रजीत सिंह
स्वतंत्र प्रभार : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
क्रियान्वयन मंत्रालय
योजना मंत्रालय
राज्यमंत्री : संस्कृति मंत्रालय

डॉ. जितेंद्र सिंह
स्वतंत्र प्रभार : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू-विज्ञान मंत्रालय
राज्यमंत्री : Prime Minister's Office
कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
परमाणु ऊर्जा विभाग
अंतरिक्ष विभाग

श्री अर्जुन राम मेघवाल
स्वतंत्र प्रभार : कानून एवं न्याय मंत्रालय
राज्यमंत्री : संसदीय कार्य मंत्रालय

श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव
स्वतंत्र प्रभार : आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय (आयुष)
राज्यमंत्री : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री जयंत चौधरी
स्वतंत्र प्रभार : कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
राज्यमंत्री : शिक्षा मंत्रालय

श्री जितिन प्रसाद
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री श्रीपद येस्सो नाइक
बिजली मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

श्री पंकज चौधरी
वित्त मंत्रालय

श्री कृष्ण पाल
सहकारिता मंत्रालय

श्री रामदास अठावले
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

राज्य मंत्री

श्री रामनाथ ठाकुर
कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्रालय

श्री नित्यानंद राय
गृह मंत्रालय

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

श्री वी. सोमन्ना
जल शक्ति मंत्रालय
रेल मंत्रालय

डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी
ग्रामीण विकास मंत्रालय
संचार मंत्रालय

डॉ. सत्यपाल सिंह बघेल
पशुपालन, डेयरी और
मत्स्य पालन मंत्रालय,
पंचायती राज मंत्रालय

सुश्री शोभा कारान्दलाजे
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्री कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय,
विदेश मंत्रालय

श्री बी. एल. वर्मा
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

श्री शांतनु ठाकुर
पत्तन, पोत परिवहन और
जलमार्ग मंत्रालय

श्री सुरेश गोपी
पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय

डॉ. एल. मुरुगन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय

श्री अजय टम्टा
सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय

श्री बंदी संजय कुमार
गृह मंत्रालय

श्री कमलेश पासवान
ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री भागीरथ चौधरी
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

श्री सतीश चंद्र दुबे
कोयला मंत्रालय
खान मंत्रालय

श्री संजय सेठ
रक्षा मंत्रालय

श्री रवनीत सिंह
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
रेल मंत्रालय

श्री दुर्गादास उइके
जनजातीय कार्य मंत्रालय

श्रीमती खडसे रक्षा निखिल
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

राज्य मंत्री

श्री सुकांता मजूमदार
शिक्षा मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

श्रीमती सावित्री ठाकुर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

श्री तोखन साहू
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

श्री राज भूषण चौधरी
जल शक्ति मंत्रालय

श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय

श्री हर्ष मल्होत्रा
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

श्री मुरलीधर मोहोल
सहकारिता मंत्रालय
नागरिक विमानन मंत्रालय

श्री जॉर्ज कुरियन
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय

श्री पबित्रा मार्गेरिटा
विदेश मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय

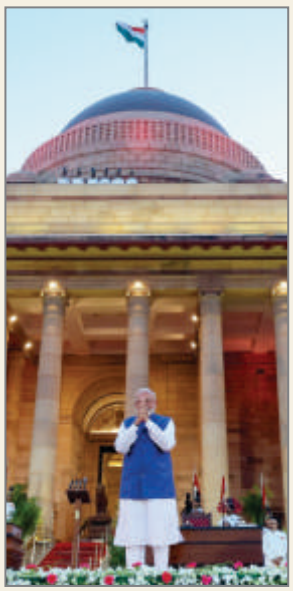

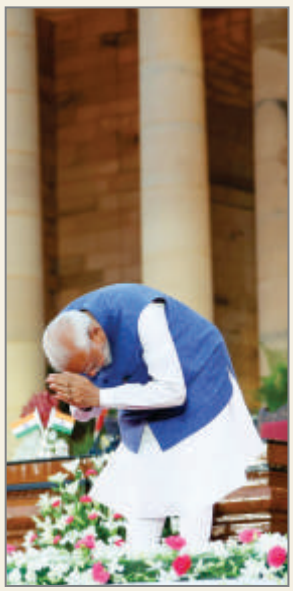

देश की आवाज के साथ बुलंद प्रदेश की आवाज ...

"मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नव- निर्वाचित सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप नई संसद में राजस्थान के जनहितैषी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और समाज सेवा के उद्देश्य को निभाते हुए जनसेवा करेंगे।"

संसद में राजस्थान

अलवर	जोधपुर	बीकानेर	अजमेर	कोटा
श्री भूपेन्द्र यादव	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	श्री अर्जुनराम मेघवाल	श्री भागीरथ चौधरी	श्री ओम बिरला

	संसदीय क्षेत्र		सांसद का नाम
1.	अजमेर	:	श्री भागीरथ चौधरी
2.	अलवर	:	श्री भूपेन्द्र यादव
3.	बांसवाड़ा	:	श्री राजकुमार रोत
4.	बाड़मेर	:	श्री उम्मेदा राम बेनीवाल
5.	भरतपुर	:	श्रीमती संजना जाटव
6.	भीलवाड़ा	:	श्री दामोदर अग्रवाल
7.	बीकानेर	:	श्री अर्जुनराम मेघवाल
8.	चित्तौड़गढ़	:	श्री चन्द्रप्रकाश जोशी
9.	चूरु	:	श्री राहुल कस्वां
10.	दौसा	:	श्री मुरारीलाल मीना
11.	गंगानगर	:	श्री कुलदीप इन्दौरा
12.	जयपुर	:	श्रीमती मंजू शर्मा
13.	जयपुर ग्रामीण	:	श्री राव राजेन्द्र सिंह

	संसदीय क्षेत्र		सांसद का नाम
14.	जालौर	:	श्री लुम्बाराम
15.	झालावाड़ - बारां	:	श्री दुष्यंत सिंह
16.	झुंझुनूं	:	श्री बृजेन्द्र सिंह ओला
17.	जोधपुर	:	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
18.	करौली - धौलपुर	:	श्री भजनलाल जाटव
19.	कोटा	:	श्री ओम बिरला
20.	नागौर	:	श्री हनुमान बेनीवाल
21.	पाली	:	श्री पी.पी. चौधरी
22.	राजसमंद	:	श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़
23.	सीकर	:	श्री अमराराम
24.	टोंक - सवाईमाधोपुर	:	श्री हरीशचंद्र मीना
25.	उदयपुर	:	श्री मन्नालाल रावत

दिल्ली डायरी

शुभकामनाएं

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में 17 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके राजकीय निवास पर शिष्टाचार भेंट की।

केन्द्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 9 जून, 2024 सायं राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। श्री शर्मा ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरेगा तथा विकास की राहों पर तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन व सतत प्रयासों के अनुरूप भारत समग्र विकास के सुपथ पर अविराम गतिशील रहेगा व 'विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करते हुए देश वैश्विक पटल पर महाशक्ति के रूप में उभरेगा।

राजस्थान हाउस दौरा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड़ स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को कार्य में और अधिक गति लाते हुए तय समय-सीमा में इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समय-सीमा के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

डॉ. शिवराम मीना
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

युवाओं का बढ़ा विश्वास

भर्ती, परीक्षाओं की कसौटी पर खरी उतर रही सरकार

नवीन कुमार आनंदकर
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं की शुचिता व गोपनीयता के दृष्टिगत विभिन्न नए नवाचार किए गए है, परिणाम स्वरूप इस वर्ष आयोजित की गई सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2023 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड पीटीआई परीक्षा-2023 निर्बाध रूप से सपंन्न हुई। परीक्षा के लिए की गई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं व राज्य सरकार की सतर्कता व सजगता का परिणाम है कि परीक्षा आयोजन के दौरान व बाद किसी भी प्रकार की गडबड़ी अथवा अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। परीक्षाओं का शुचितापूर्ण आयोजन पेपर लीक एवं डमी कैंडिडेट्स की आशंका झेल रहे प्रदेश के युवाओं का मनोबल बढ़ाने एवं निष्पक्ष चयन का आश्वासन देने वाला रहा।

आयोग द्वारा लागू किए गए सुरक्षात्मक उपाय व नवाचार

परीक्षाओं के शुचिता पूर्ण आयोजन एवं डमी अभ्यर्थियों की संभावना को रोकने के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग का नमूना भी अटेंडेंस शीट पर लिया जाना शुरू किया गया है। इसी प्रकार अटेंडेंस शीट पर अभ्यर्थी की स्पष्ट व बड़ी फोटो प्रिंट की जा रही है, ताकि परीक्षा केन्द्र पर वीक्षकों द्वारा अभ्यर्थी की पहचान पूर्णतः सुनिश्चित करते हुए डमी अभ्यर्थियों की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही आयोग द्वारा कार्यप्रणाली के संवर्धन तथा काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहन जांच के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रमानुसार निरंतर प्रशिक्षण सत्र कार्यालय समय में आयोजित किए जा रहे हैं। अभिस्तावना प्रेषित करने से पूर्व भी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र की जांच आयोग के पास उपलब्ध आयोग के रिकॉर्ड से की जा रही है। किसी भी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में पुनः जांच कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पकड़े गए डमी व मूल अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराए जा रहे हैं।

युवा वर्ग को भर्तियों की सौगात

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त अभ्यर्थना अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस वर्ष अभी तक कुल 1544 पदों के लिए 15 भर्ती विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। साथ ही इनकी प्रस्तावित परीक्षा दिनांक भी आयोग द्वारा घोषित कर दी गई है।

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग की परीक्षाओं के संदर्भ में विगत समय से अभ्यर्थियों की अपेक्षा रही है कि संघ लोक सेवा आयोग की भांति राजस्थान लोक सेवा द्वारा भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी किया जाए ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु समुचित समय मिल सके। अभ्यर्थियों की इन्ही भावनाओं के दृष्टिगत आयोग द्वारा परीक्षा की प्रस्तावित परीक्षा दिनांक विज्ञापन के साथ अथवा कुछ समय के बाद ही जारी करते हुए नियत कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं

> "युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवा में समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रिक्तियों को भरा जाएगा। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने हेतु इस वर्ष लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां कर रही है। साथ ही, युवाओं को न्याय प्रदान करने के लिए पेपरलीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी इन मामलो में निरंतर दोषियों को गिरफ्तार कर रही है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। युवाओं की ऊर्जा और क्षमताओं का सही उपयोग के लिए नई दिशा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है।"

यूपीएससी परीक्षा-2023 में राजस्थान से चयनित युवाओं ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा-2023 में राजस्थान से चयनित युवाओं ने मुलाकात की। श्री शर्मा ने युवाओं को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को साफा पहनाकर, शॉल ओढाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान चयनित युवाओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार, महिला सशक्तीकरण, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य की स्थिति सुधारने सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार भी साझा

किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक श्री यू आर साहू सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

के आयोजन का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2024 एवं 2025 में प्रस्तावित परीक्षा दिनांक भी जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा प्राप्त अर्थना अनुसार भर्ती परीक्षा कैलेण्डर को भी अद्यतन किया जा रहा है। आयोग द्वारा घोषित आगामी परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षाएं :-

जून-जुलाई माह

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा -2023 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 एवं 21 जुलाई 2024 को किया जाएगा। अन्य परीक्षाओं में खोज एवं उत्खनन अधिकारी तथा संग्रहाध्यक्ष (पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 का आयोजन 19 जून 2024, सहायक अभियंता-यांत्रिकी (भू-जल विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 का आयोजन 30 जून 2024 एवं विधि रचनाकार (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 14 जुलाई 2024 को किया जाना प्रस्तावित है।

अगस्त-सितंबर माह

पुरालेखपाल, सहायक पुरालेखपाल, शोध अध्येता, रसायनज्ञ एवं शोध अधिकारी (कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 3 व 4 अगस्त 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 25 अगस्त 2024 एवं सहायक आचार्य (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 8 से 12 सितंबर एवं 14 व 15 सितंबर 2024 को किया जाना प्रस्तावित है।

अक्टूबर-दिसंबर माह

प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों हेतु प्राध्यापक-विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 17 नवंबर से 21 नवंबर 2024 तक एवं वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2025 : फरवरी-जून माह

सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 19 जनवरी 2025 तथा पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-द्वितीय परीक्षा-2024 का आयोजन 16 फरवरी 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा-2024 का आयोजन 23 मार्च 2025 एवं कृषि अधिकारी परीक्षा-2024 का आयोजन 20 अप्रेल 2025 को किया जाना प्रस्तावित किया गया है। संस्कृत शिक्षा (कॉलेज विभाग) हेतु शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 4 से 6 मई 2025 एवं सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य परीक्षा)-2024 का आयोजन 1 जून 2025 को किया जाना प्रस्तावित है।

नारी शक्ति द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनन्दन

"महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आत्मनिर्भर, सशक्त एवं शिक्षित महिलाएं ही प्रगतिशील समाज की पहचान है। राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाने और आधी आबादी को उनका हक देने के लिए कृतसंकल्पित है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय से महिलाएं राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षण कार्य कर सकेंगी और अध्ययनरत बच्चों की ममत्व भाव से देखभाल भी कर सकेंगी।"

उत्कृष्ट विद्युत-जल प्रबन्धन से मिली गर्मी में राहत

पानी और बिजली के बिना आम जनजीवन की कल्पना भी बेमानी है। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान बिजली की मांग अत्यधिक बढ़ गयी थी। गर्मियों में विद्युत मांग बढ़ने से लोड ज्यादा होना यह हर वर्ष की सामान्य स्थिति है, लेकिन इस बार कई जगह 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान होने के कारण बिजली का लोड अत्यधिक बढ़ गया। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समय पर सारी स्थिति को भांपते हुए प्रदेश में बिजली की मांग 3 हजार 777 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने तथा 147 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दूसरे राज्यों को लौटाने जैसी चुनौतियों के बावजूद आमजन के लिए पर्याप्त बिजली का प्रबन्ध किया।

बिजली के साथ ही प्रदेशवासियों के लिए पानी की समुचित उपलब्धता और पशुओं के लिए दवा-चारे-पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे तंत्र को अत्यधिक सक्रिय स्थिति में रखा।

पीएचईडी और विद्युत वितरण निगमों को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए अधिकारियों की लगातार बैठकें लेकर बिजली और पानी की प्रभावी आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को पीक लोड की स्थिति में भी बिजली कटौती और पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने बिजली की बढ़ी हुई मांग के अनुसार एक्सचेंज के माध्यम से उचित दरों पर बिजली खरीद करने, बंद पड़ी विद्युत उत्पादन इकाइयों के संचालन के निर्देश दिए। उनके निर्देशों की अनुपालना में पीएचईडी एवं ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य स्तर एवं जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से नियमित रूप से मॉनिटरिंग की गई और आमजन की समस्याओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। साथ ही, उच्च अधिकारियों सहित सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मुस्तैद किया गया।

पशुधन एवं गोवंश के लिए पानी-दवा की समुचित व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गोपालन विभाग के माध्यम से समस्त जिला कलक्टर एवं जिला स्तरीय गोपालन समिति के अध्यक्षों को जिलों में संचालित पीएचईडी विभाग एवं अन्य जल प्रदाता एजेंसी के सहयोग से अविलम्ब पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन विभाग की ओर से गोशालाओं में गोवंश की चिकित्सा के लिए आपातकालीन औषधियां एवं सर्जिकल उपकरण खरीदने के लिए जिलों को बजट भी उपलब्ध करवाया गया।

मैराथन बैठक लेकर एक-एक जिले की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पानी-बिजली सहित विकास के अन्य विषयों पर सभी जिलों के प्रभारी सचिवों एवं विभागीय उच्चाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में संभागीय आयुक्त एवं सभी जिला कलक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिवों से फीडबैक लेते हुए एक-एक जिले में पानी-बिजली एवं विकास के विभिन्न विषयों पर कार्यस्थिति और लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन को बिजली और पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। जिस भी दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है, एक्सचेंज से खरीद कर राज्य सरकार आमजन को उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने सभी प्रभारी सचिव को निर्देश दिए कि अपने प्रभार वाले जिले के दौरे को औपचारिक समीक्षा बैठकों तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि फील्ड में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का औचक निरीक्षण भी सुनिश्चित करें।

ऊर्जा संरक्षण के लिए अभियान चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्र श्री भजनलाल शर्मा के अनुसार पानी और बिजली मूलभूत एवं सीमित संसाधन हैं एवं इनकी बचत ही इनके उत्पादन के समान है। उन्होंने अधिकारियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए आमजन को बिजली और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए।

माँ के साथ
‘एक पेड़ मां के नाम’

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 23 जून से प्रारम्भ अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में मुख्यमंत्री आवास पर अपनी माताजी श्रीमती गोमती देवी के साथ बेल का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि “पेड़ हमारे परम मित्र हैं और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ ही पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं।” उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण करें तथा पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा रखने में अपना योगदान दें।गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया था। उन्होंने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाते हुए देशवासियों से आग्रह किया था कि वे सभी अपनी माताजी के नाम पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं।

7 करोड़ पौधारोपण का महाभियान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा पर्यावरण दिवस, 5 जून को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधे आमजन को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि और 1 करोड़ पौधे ओरण एवं चरागाह भूमि पर लगाए जाएंगे।

धूप में गमछा बांध देसी अंदाज में दिखे मुख्यमंत्री

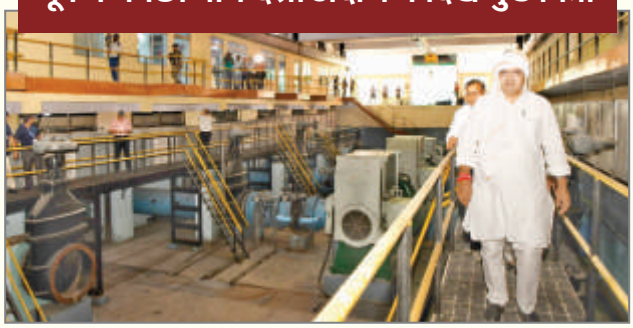

भरी दोपहरी में रामनिवास बाग व जवाहर सर्किल पम्प हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा देशी अंदाज में नजर आए। उन्होंने सिर पर गमछा बांधकर तेज धूप में रामनिवास बाग व जवाहर सर्किल पम्प हाउस में जलापूर्ति की बड़ी-बड़ी मशीनों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां स्थित कंट्रोल रूम में जाकर कम्प्यूटर द्वारा पानी सप्लाई की प्रणाली को बारीकी से समझा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत पर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

जल स्रोतों के मार्ग में आने वाले अतिक्रमण हटवाए

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मानसून से पहले जल संग्रहण एवं संचयन के ढांचों (वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने के साथ ही परंपरागत पेयजल एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भू-जल स्तर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 अभियान के कार्यों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

जीवों के प्रति दर्शाया दया भाव-परिण्डे बांध आमजन को किया प्रेरित

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पशु-पक्षियों के प्रति दया भाव और संवेदनशीलता दिखाते हुए पार्क में पक्षियों के लिए पानी के परिण्डे बांधे और उन्हें दाना डाला। मुख्यमंत्री ने आमजन को शीतल पानी की प्याऊ लगवाने और पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था जैसे पुनीत कार्यों में आगे आने के लिए प्रेरित किया।

हेमेन्द्र सिंह
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

अंगदान

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में राजस्थान अव्वल

अंगदान व अंग प्रत्यारोपण में रहेगी पूर्ण पारदर्शिता

आकांक्षा शर्मा
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

नेन प्राप्यते स्वर्गा दानेन सुखमश्नुते ।
इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवरू ॥

अर्थात दान से स्वर्ग प्राप्त होता है, दान से सुख भोग्य बनते हैं। यहां और परलोक में इन्सान दान से पूज्य बनता है। भारत में दान एवं परमार्थ का इतिहास रहा है जहां क्षमतानुसार हर व्यक्ति के पास सदैव देने को कुछ न कुछ जरूर होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के 99वें संस्करण में अंगदान के संबंध में कही गई बाद प्रदेश के लोगों के मन को छू गई और प्रदेशवासियों ने 35 हज़ार 764 से अधिक अंगदान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर वर्षारम्भ में राजस्थान को अव्वल स्थान पर लाकर इतिहास रच दिया।

अंगदान के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में राजस्थान देश भर में अव्वल

राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाया जाए ताकि अंग प्रत्यारोपण के संबंध में अंगों की उपलब्धता समुचित मात्रा में हो और हर जरूरतमंद को यह उपलब्ध हो सके।

राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जन-जन तक अंगदान संबंधी विशेष जागरूकता अभियान/कार्यक्रम चला रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग घर-घर जाकर आशा, एएनएम के माध्यम से एवं विभिन्न स्वास्थ्य शिविर के जरिए लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी "मोदी की गारंटी" के साथ पहुंचे विकास रथ ने अंगदान के लिए आमजन को प्रेरित किया और अंगदान के लाभ एवं परमार्थ के बारे में विस्तार से मानवीय पहलू के साथ समझाया तो राजस्थानवासियों ने भी उदार हृदय के साथ अंगदान देहदान की शपथ लेकर प्रदेश के गौरव को बढ़ाया।

पीएम मोदी ने मन की बात में कहा था 'आज देश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है लेकिन हमारे देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद हैं जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी अंगदान करने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी कारण राज्यों के अधिवास की शर्त को भी हटाने का फैसला किया गया है, यानी अब मरीज देश के किसी भी राज्य में जाकर अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

लाखों लोगों को प्रतीक्षा

भारत में ही प्रतिवर्ष लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्यारोपण की संख्या और अंग उपलब्ध होने की संख्या के बीच एक बड़ा अंतराल है। दान किये जा सकने वाले अंग गुर्दे, फेफड़े, आंख, यकृत, कॉर्निया, छोटी आंत, त्वचा के ऊतक, हड्डी के ऊतक, हृदय वाल्व और शिराएं हैं। अंगदान उन व्यक्तियों को किया जाता है, जिनकी बीमारियां अंतिम अवस्था में होती हैं तथा जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।

अंगदान से तात्पर्य

अंगदान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति (जीवित या मृत, दोनों) से स्वस्थ अंगों और ऊतकों को लेकर किसी अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। प्रत्यारोपित होने वाले अंगों में दोनों गुर्दे (किडनी), यकृत (लीवर), हृदय, फेफड़े, आंत और अग्नाश्य शामिल होते हैं। जबकि ऊतकों के रूप में कॉर्निया, त्वचा, हृदय वाल्व कार्टिलेज, हड्डियों और वेसेल्स का प्रत्यारोपण होता है।

अंगदान कौन कर सकता है?

जीवित व्यक्ति के लिए अंगदान के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। जीवित अंगदाता द्वारा एक किडनी, अग्नाश्य और यकृत के कुछ हिस्से दान किये जा सकते हैं। कॉर्निया, हृदय वाल्व, हड्डी और त्वचा जैसे

ऊतकों को प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात् दान किया जा सकता है। परंतु हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े और अग्नाशय जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण अंगों को केवल ब्रेन डेड के मामले में ही दान किया जा सकता है। कार्डियक डेथ अर्थात प्राकृतिक रूप से मरने वाले का सामान्यतः नेत्र (कॉर्निया) दान किया जाता है।

प्रदेश में हुआ 59वां अंगदान

राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तरीय ऑथोराइजेशन कमेटी और प्रत्यारोपण के लिए सलाहकार समिति गठित किए जाने के बाद कमेटी की पहली बैठक में रखे गए 11 प्रकरणों को आवश्यक जांच व प्रक्रिया के बाद एनओसी जारी कर दी गई। कमेटी द्वारा मरीज और परिजन की आवश्यक वीडियोग्राफी सहित पूरी प्रक्रिया के बाद एनओसी जारी की गई है।

तीन लोगों को मिला जीवनदान

जयपुर के नारायणा अस्पताल में प्रदेश का 59वां अंगदान हुआ। गुजरात मूल हाल जयपुर निवासी 44 वर्षीय शुक्ला तेजस उपेन्द्र कुमार का 21 मई को एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें 24 मई को ब्रेन डेड घोषित किया गया। चिकित्सकों तथा ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर की समझाइश के बाद परिजन उनके अंगदान के लिए तैयार हुए। इसके बाद एक किडनी व लीवन सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भेजा गया तथा एक किडनी का प्रत्यारोपण नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में किया गया। इस प्रकार उपेन्द्र कुमार तीन लोगों को जीवनदान दे गए।

अंग प्रत्यारोपण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया आवश्यक कदम

चिकित्सा विभाग की ओर से मानव अंग प्रत्यारोपण के मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डोनर और रिसीवर की यूनिक नोटो-आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बिना प्रत्यारोपण संभव नहीं होगा। यह आईडी प्रत्यारोपण सर्जरी के 48 घंटों के भीतर जनरेट करनी होगी।

अंगदान को लेकर लोगों में बढ़ती जागरूकता बदलते भारत की तस्वीर है एवं अंगदान की शपथ लेने वाली प्रत्येक महिला और पुरुष का संकल्प किसी के जीवन, किसी के परिवार और देश के लिए अमूल्य है।

भारत में अंगों की कमी की स्थिति

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार भारत में अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों और उपलब्ध अंगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अनुमान है कि हर साल लगभग 1.8 लाख लोग गुर्दे की विफलता से पीड़ित होते हैं, जबकि गुर्दे के प्रत्यारोपण की संख्या केवल 6000 के आसपास है। भारत में हर साल लगभग 2 लाख मरीज लीवर की विफलता या लीवर कैंसर से मरते हैं, जिनमें से लगभग 10-15% को समय पर लीवर प्रत्यारोपण से बचाया जा सकता है। इसलिए भारत में हर साल लगभग 25-30 हजार लीवर प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, लेकिन केवल लगभग 1500 लिवर प्रत्यारोपण ही किए जा रहे हैं। इसी तरह हर साल लगभग 50,000 लोग दिल की विफलता से पीड़ित होते हैं, लेकिन भारत में हर साल केवल 10 से 15 हृदय प्रत्यारोपण किए जाते हैं। कॉर्निया के मामले में, हर साल लगभग 25,000 प्रत्यारोपण किए जाते हैं, जबकि जरूरत 1 लाख की है।

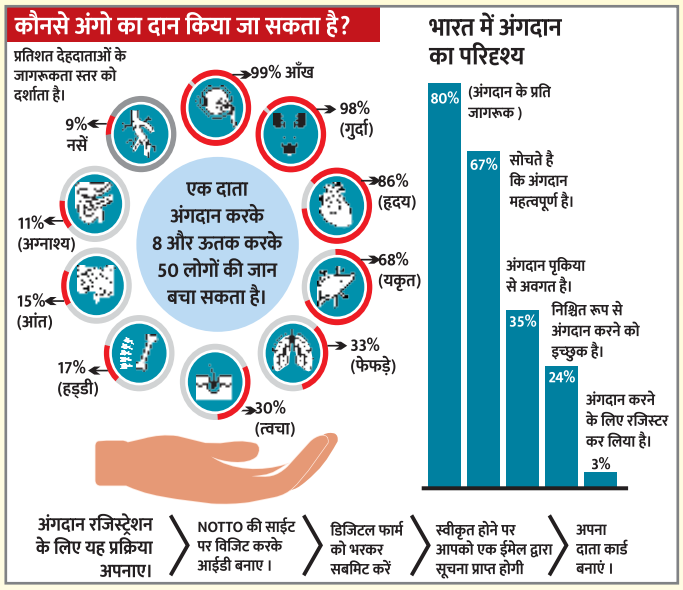

इन प्रदेशवासियों ने बढ़ाया गौरव

खैराबाद पंचायत समिति की आशा सहयोगिनी **मीना कुमारी सेन** ने अंगदान एवं देहदान का संकल्प लिया ताकि उनके बाद भी उनके शरीर के अंग जरूरतमंद रोगियों के काम आ सके।

पीपाखेड़ी के **प्रेमचंद चौहान** ने भी शिविर में प्रेरित होकर अंगदान का संकल्प लिया। वे चाहते हैं कि उनके बाद उनकी आंखों से भी कोई इस सुंदर दुनिया को देख सके।

आशा सहयोगिनी **श्रीमती रामकन्या** स्वयं दिव्यांग हैं लेकिन उन्होंने अंगदान का संकल्प लेकर समस्त समाज को अपने सेवा भाव एवं दान से ऋणी बना दिया है।

श्री बलवंत सिंह शक्तावत ने शिविर में अंगदान एवं देहदान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का संकल्प लिया ताकि उनका शरीर मृत्यु उपरान्त भी जिन्दा रहे।

प्रथम प्राथमिकता ...

सुरक्षित प्रदेश, सुरक्षित युवा, सुरक्षित महिला

सपना शाह
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसम्बर 2023 को कार्यभार ग्रहण के साथ ही कहा था कि 'महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा था कि 'गत वर्षों में महिला सुरक्षा प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। उन्होंने निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जाए ताकि प्रदेश की मातृशक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही, असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी अपराधों की पूर्णतया रोकथाम हो सके।'

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा था कि प्रदेश में गत वर्षों में वृहद स्तर पर सामने आईं पेपरलीक की घटनाओं से प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूटा और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं के प्रति उनका विश्वास कमजोर हुआ है। इस विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने गत पांच वर्षों में हुए पेपरलीक के मामलों की जांच के लिए 16 दिसम्बर को ही एसआईटी गठित की। जिससे प्रदेश की युवा शक्ति के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलने और भविष्य में पेपरलीक की घटनाएं रोकना सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अपने पहले कार्य दिवस पर मुख्यमंत्री ने संगठित अपराधों के उन्मूलन पर प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति एवं सुशासन की पुनर्स्थापना के लिए संगठित अपराध का उन्मूलन जरूरी है। उन्होंने इसके लिए एडीजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष कार्यदल (एंटी गैंगस्टर टास्क फॉर्स) का गठन किया, जो सभी प्रकार के गैंगस्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेगी।

स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम

राजस्थान में गत पांच वर्षों में पेपरलीक मामलों की त्वरित जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने महानिदेशक पुलिस को आदेश जारी कर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का गठन का निर्णय किया। यह टीम पेपर लीक के सभी मामलों की गहनता से जांच कर रही है और भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के पुख्ता प्रयास सुनिश्चित हो रहे हैं। वर्ष 2021 में 5 बड़े पेपर लीक हुए, वर्ष 2022 में 10 तथा वर्ष 2023 में 5 पेपर लीक हुए। वहीं नई राज्य सरकार के गठन के बाद जो भी पेपर हुए हैं उनमें पेपरलीक का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकार भर्ती परीक्षाओं की निगरानी डीजीपी एव मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में करवा रही है।

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल

"प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय' के ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान पुलिस कर्मठता से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है।"

भर्ती परीक्षा 2021, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट भर्ती परीक्षा 2021, कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) भर्ती परीक्षा 2020, हाई कोर्ट लिपिक भर्ती परीक्षा 2020 की जांच की जा रही है। प्रदेश में एसआईटी के गठन के बाद से अब तक 10 प्रकरणों में चार्जशीट पेश की जा चुकी है, 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 70 आरोपी अभी भी जेल में हैं और 29 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी हैं।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स

प्रदेश में संगठित अपराधों को रोकने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गयी है। इस फोर्स का गठन अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में किया गया है। यह प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने और संगठित अपराधों की रोकथाम करने के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल के निर्देश पर 15 से 31 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान में अवैध वाहनों के साथ ही खनिजों के अवैध भण्डारण पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए जब्ती की गयी। इस दौरान करीब ढाई लाख मीट्रिक टन खनिज जब्त किये गए। जब्त खनिजों के चोरी या खुर्द-बुर्द होने की आशंका से संबंधित थानों को सुपुर्दगी की गयी और नीलामी और राशि वसूली जैसी कार्यवाही की गयी। साथ ही बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ भी सघन अभियान चलाया गया।

75वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में सलामी लेते मुख्यमंत्री

पूरे प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे मिलावाटखोरों के खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की टीमों द्वारा 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान चलाया गया। प्रदेश में नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों पर उनके अवैध कब्जों को ध्वस्त करने, संपत्ति फ्रीज करने जैसी कार्रवाई की जा रही है।

महिला उत्थान और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही प्रदेश की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की सौगातें दी जिससे लाभान्वित होकर महिलाएं सशक्त एवं समर्थ हो सकें। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। राज्य के 1024 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना कर महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति की गयी है। साथ ही वूमेन हेल्प डेस्क, रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए लाडली सुरक्षा योजना के तहत राज्य के प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना जैसे फैसले किए गए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिये नियंत्रण किया जा रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाकर महिलाओं का सफर और भी अधिक सुरक्षित बनाने की एक पहल की गयी है।

सभी क्षेत्रों में महिला उत्थान की राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 6500 रुपये की गई। महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने के लिए **MAA वाउचर योजना** की शुरूआत की गई। साथ ही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। पुलिस भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के स्वीकृति भी दी गयी. इसी प्रकार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर उसे एक लाख रूपये का सेविंग बॉण्ड दिया जायेगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए देश में चल रही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 11 लाख 24 हज़ार महिलाओं के परिवारों की आय को एक लाख रुपये वार्षिक तक बढाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में भी 2 लाख 80 हजार से ज्यादा महिलाएं और उनका परिवार एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत 01 जनवरी 2024 से प्रदेश की सभी जरूरतमंद महिलाओं को सिर्फ 450 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश के करीब 76 लाख परिवारों का जीवन आसान होगा। महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरा प्रदेश और प्रदेशवासी सुरक्षित और खुशहाल महसूस कर रहे हैं।

"आम" नहीं बेहद खास है बांसवाड़ा का आम

डॉ. कमलेश शर्मा
संयुक्त निदेशक

फलों के राजा की 18 स्थानीय और 28 ख्यातनाम प्रजातियों की पहुंच देशभर में

अपने बेनजीर शिल्प-स्थापत्य और अनूठी परंपराओं के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध राजस्थान का दक्षिणांचल बांसवाड़ा जिला अपनी प्राकृतिक विविधता और वृक्षोपज के लिए भी जाना-पहचाना जाता है। और जब प्रकृति के अनुपम उपहार फलों की बात हो तो गर्मियों में आने वाले फलों के राजा "आम" का नाम "खास" है। वागड़ गंगा माही से सरसब्ज बांसवाड़ा जिला फलों के उत्पादन के लिए भी सर्वथा उपयुक्त है और यही वजह है कि यहां पर आम की कुल 46 प्रजातियों की हर साल बंपर पैदावार होती है।

इस वर्ष भी गर्मियों के दिनों में इन सभी प्रजातियों के आम बाजार में भरपूर उपलब्ध हुए हैं और वागड़वासियों ने इसके अमृतमयी रस का लुत्फ उठाया। यहां के आम और आम के उत्पाद मुख्य रूप से समीपस्थ गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों तक भी जाते हैं।

देसी व उन्नत किस्म की 46 प्रजातियां

देखा जाए तो बांसवाड़ा जिले में परंपरागत रूप से पैदा होने वाली देसी रसीले आम की 18 प्रजातियों के साथ देशभर में पाए जाने वाली उन्नत किस्म की 28 अन्य प्रजातियों का भी उत्पादन होता है। जिले में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा संचालित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरवट, बांसवाड़ा में भी बड़े क्षेत्र में "मातृ वृक्ष बगीचे" स्थापित हैं जिनमें देशी व उन्नत विभिन्न किस्म के कुल 46 प्रजातियों के आमों की किस्मों का संकलन है। यहां पर आम के ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर किसानों को उपलब्ध करवाये जाते हैं। उद्यान विभाग के अधीन गढ़ी कस्बे में राजहंस नर्सरी भी स्थापित है, जहां से विभिन्न उन्नत किस्मों के आम के पौधे किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

इन प्रजातियों का होता है बड़े पैमाने पर उत्पादन

जिले के विभिन्न बगीचों में आम की किशन भोग, बोम्बे ग्रीन, बोम्बई, केसर, राजस्थान केसर, फजली, मूलागो, बैगनपाली, जम्बो केसर गुजरात, स्वर्ण रेखा, बंगलौरा, नीलम, चौसा, दशहरी, मनकुर्द, वनराज, हिमसागर, जरदालु, अल्फांजो, बजरंग, राजभोग, मल्लिका, लंगड़ा, आम्रपाली, फेरनाड़ी, तोतापूरी, रामकेला आदि 28 प्रजातियों का तो उत्पादन होता ही है, साथ ही देसी रसीले आम की 18 प्रजातियों यथा टीमुरवा, आंगनवाला, देवरी के पास वाला, कसलवाला, कुआवाला, आमड़ी, काकरवाला, लाडुआ, हाडली, अनूप, कनेरिया, पीपलवाला, धोलिया, बारामासी, बनेसरा, सागवा, कालिया, मकास आदि प्रजातियों का भी उत्पादन होता

है। सबसे खास बात है कि आम की सभी 18 स्थानीय प्रजातियां रेशेदार हैं और इनका उत्पादन सिर्फ दक्षिण राजस्थान में ही होता है।

पाकिस्तान की नूरजहां और ढाई किलो का डायमंड भी

पाकिस्तान का चौसा भी यहां पैदा होता है जिन्हें नूरजहां नाम दिया गया है। दूसरा ढाई किलो के एक आम की वैरायटी भी यहां उत्पादित होती है जिसे डायमंड नाम से जाना जाता है, हालांकि इनका उत्पादन सीमित है।

विदेशों में भी है यहां के आम की मांग

बांसवाड़ा के आम की मांग विदेशों तक भी है। अरब देशों में रहने वाले यहां के प्रवासी भी आम की ऋतु में इन्हें ले जाना या मंगवाना नहीं भूलते। यहां के आम तथा आम के विविध उत्पाद केनेडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा यूरोपीयन देशों में नागर, नैमा और बोहरा समुदाय के लोगों द्वारा अपने-अपने रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंचाये जाते हैं।

फलोत्पादन का 86 प्रतिशत सिर्फ आम

उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों को देखें तो उद्यानिकी फसलों की दृष्टि से बांसवाड़ा जिला धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। जिले में 6 हजार 316 हैक्टेयर क्षेत्र में फल एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। जिलेभर में फलों का कुल उत्पादन 45 हजार 443 मीट्रिक टन होता है जिसमें आम, आंवला, नींबू, अमरूद, पपीता, अनार, चीकू तथा अन्य हैं। आम उत्पादन के क्षेत्र को देखें तो जिले के कुल फल उत्पादन क्षेत्र 3 हजार 480 हैक्टेयर में से 3 हजार 115 हैक्टेयर में आम का उत्पादन होता है जो कि कुल फलोत्पादन क्षेत्र का 90 प्रतिशत है। इसी प्रकार फलों के कुल 45 हजार 443 मीट्रिक टन उत्पादन के मुकाबले अकेले आम का उत्पादन 39 हजार 120 मीट्रिक टन है जो कुल फलोत्पादन का 86 प्रतिशत है। इस उत्पादन में स्थानीय स्तर पर छोटे किसानों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन शामिल नहीं है।

पहले "मेंगो फेस्टिवल" से मिली आम को पहचान

राजस्थान का पहला मेंगो फेस्टिवल 7 से 9 जून, 2019 तक "बांसवाड़ा मेंगो फेस्टिवल-2019" के नाम से आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यहां पैदा होने वाले आम की स्थानीय और उन्नत किस्मों से जनसामान्य को रूबरू कराना, किसानों को आम के बगीचे लगाने के लिए प्रेरित करना तथा उद्यमियों को आम प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके साथ ही "मेंगो हब" के रूप में विकसित हो रहे बांसवाड़ा जिले का नाम राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की सोच भी इस आयोजन की पृष्ठभूमि में थी, जो सफल रही। कोरोना महामारी के कारण इसके बाद के 2 वर्षों में मेंगो फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो पाया। इसके बाद बांसवाड़ा के आम को पहचान समीपस्थ गुजरात राज्य के गांधीनगर में 27 व 28 मई, 2022 आयोजित हुए राष्ट्रीय मेंगो फेस्टिवल में मिली जहां पर राजस्थान से मात्र बांसवाड़ा जिले की स्टॉल लगाई गई। इसी प्रकार वर्ष 2022 व 2023 में मेंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया।

लॉकडाउन में घर-घर पहुंचाया आम

कोरोना महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान बांसवाड़ा में उपजने वाले आमों का लुत्फ उठाने से वागड़वासी वंचित न रह जाएं, इस दृष्टि से तत्कालीन जिला कलक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की पहल पर जिला पर्यटन उन्नयन समिति एवं सहकारी उपभोक्ता भंडार बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में श्री एकलिंगनाथ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं न्यू राज फार्म के माध्यम से घर-घर आम पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

कुशल प्रबंधन से हर घर 24 x 7 बिजली

अभिषेक जैन
सहायक निदेशक

बिजली के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर हो या दुकान, खेत हो या खलिहान, उद्योग हों अथवा वाणिज्यिक संस्थान। सभी के लिए बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में एनर्जी सेक्टर की अहम भागीदारी है और किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। प्रदेश के आर्थिक विकास में सुदृढ़ विद्युत तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। गर्मी के इस सीजन में हीटवेव के कारण तापमान अपने चरम पर रहा। इसके चलते बिजली की मांग में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार के समय रबी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए बैंकिंग सिस्टम के तहत ली गई करीब 1.45 लाख मेगावाट बिजली को चुकाने की जिम्मेदारी अलग से है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी राज्य सरकार ने उत्पादन, वितरण एवं प्रसारण, विद्युत तंत्र से जुड़े इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों का बेहतर प्रबंधन किया और उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी।

अर्जित किया बेहतर प्लांट लोड फैक्टर

राज्य में गत वर्ष की अपेक्षा इस साल मई माह में अत्यधिक गर्मी पड़ी। इससे गत वर्ष की तुलना में बिजली की खपत औसतन लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ गई। बीते वर्ष मई माह की कुल खपत 82,072 लाख यूनिट थी जो इस साल प्रचंड गर्मी एवं लू के थपेड़ों के कारण 1,02,665 लाख यूनिट हो गई। मई माह की 30 तारीख को तो अधिकतम मांग 17,567 मेगावाट तक पहुंच गई। एकाएक बढ़ी बिजली की इस मांग को पूरा करना निश्चय ही टेढ़ी खीर था। ऐसे में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के मार्गदर्शन में ऊर्जा विभाग ने कमर कसी और अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक ने उत्पादन, वितरण एवं प्रसारण निगमों के प्रबंध निदेशकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित रूप से मांग, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण की स्थिति की सघन मॉनिटरिंग की।

इस राह में बड़ी चुनौती उत्पादन को बढ़ाने की थी। प्रदेश में उत्पादन निगम के अधिकतर थर्मल पावर प्लांट पुराने हैं। ऐसे में इन बिजलीघरों को लगातार चलाने और बेहतर प्लांट लोड फैक्टर अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तकनीकी कारणों से किसी इकाई से उत्पादन बाधित होने की स्थिति में उसे जल्द से जल्द पुनः सिंक्रोनाइज करने के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की गई। बेहतर गुणवत्ता युक्त

कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इन प्रयासों का परिणाम रहा कि इस वर्ष अप्रेल माह में 73.76 प्रतिशत एक्चुअल प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया गया, जबकि वर्ष 2023 के अप्रेल माह में यह 62.5 प्रतिशत ही था। इसी प्रकार इस वर्ष मई माह में वास्तविक प्लांट लोड फैक्टर 71.98 प्रतिशत अर्जित किया गया जो कि गत वर्ष इस माह में यह मात्र 63.72 प्रतिशत ही था।

बिजलीघरों को मिल रहा पर्याप्त कोयला

राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की थर्मल आधारित सभी 23 इकाइयों को निर्बाध रूप से चलाने के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। साथ ही रेलवे से भी लगातार समन्वय कर आवश्यकतानुसार रैक प्राप्त हो रही है। प्रदेश की बागडोर संभालने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के साथ इस साल जनवरी माह में ही तत्कालीन केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी से दिल्ली में मुलाकात कर प्रदेश के विद्युत गृहों को मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति करने का आग्रह किया था। राज्य सरकार के प्रयासों का सार्थक परिणाम निकला और केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य के बिजलीघरों को नियमित रूप से पर्याप्त कोयला उपलब्ध हो रहा है। इस विषम परिस्थिति में राजस्थान को कहीं भी कोयले की कमी झेलने की नौबत नहीं आई।

एक्सचेंज से खरीद कर बढ़ाई बिजली की उपलब्धता

राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की डिमांड को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी जाए। ऐसे में पीक ऑवर्स एवं नॉन पीक ऑवर्स में बिजली की अत्यधिक मांग तथा उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए 1 मई से 9 जून के मध्य एनर्जी एक्सचेंज से लगभग 19,575 लाख यूनिट बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति की गई। अकेले मई माह में ही एनर्जी एक्सचेंज से 15,436 लाख यूनिट बिजली खरीदकर पीक ऑवर्स एवं नॉन पीक ऑवर्स में उपभोक्ताओं को सतत एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

ग्रिड सब स्टेशनों के काम को दी गति

घर-घर बिजली पहुंचाने तथा व्यवधान रहित आपूर्ति के लिए प्रसारण तंत्र का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ प्रसारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी योजनाबद्ध रूप से काम किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु की डिमांड में वृद्धि की संभावना को देखते हुए ग्रिड सब स्टेशनों के काम को गति दी गई। बीते 6 माह में ही प्रदेश में 220 केवी के एक ग्रिड सब स्टेशन तथा 132 केवी के 13 जीएसएस स्थापित किए गए।

शिकायतों का किया त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए थे कि आमजन को व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भीषण गर्मी की स्थिति को देखते जलदाय विभाग के पंप हाउसों तथा जल योजनाओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए ताकि ट्रिपिंग अथवा फाल्ट के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित न हो। इसकी पालना में डिस्कॉम्स प्रबंधन ने तीनों वितरण कंपनियों के फील्ड में पदस्थापित सभी अभियंताओं एवं अधिकारियों को अवकाश नहीं लेने तथा मुख्यालय पर मौजूद रहकर आमजन की विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का हेल्पलाइन के माध्यम से सतत निराकरण करने के निर्देश दिए थे।

ऊर्जा मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डिस्कॉम्स ने भी बीते दिनों ही केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर का निरीक्षण कर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की व्यवस्था को और चाक-चौबंद बनाने की हिदायत दी। इसके साथ ही उन्होंने फील्ड में नियुक्त अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान करने तथा व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सतत मॉनिटरिंग का नतीजा रहा कि जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम में कॉल सेंटर के माध्यम से मई माह में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का प्रभावी निराकरण किया गया। जयपुर डिस्कॉम में 4 लाख 28 हजार 337 शिकायतों में से 4 लाख 26 हजार 942, जोधपुर डिस्कॉम में 3 लाख 9 हजार 524 शिकायतों में से 3 लाख 8 हजार 362 तथा अजमेर डिस्कॉम में 2 लाख 62 हजार 139 शिकायतों में से 2 लाख 62 हजार 109 समस्याओं का निराकरण कर उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री के प्रयासों से 400 मेगावाट अनावंटित बिजली राजस्थान को

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान को 2 रीजनल पूल से अनावंटित बिजली का कोटा दिया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल से हाल ही में नई दिल्ली में मुलाकात की थी। जिसके बाद केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को निर्देश दिए कि राजस्थान को दक्षिण एवं पश्चिम रीजन के अनावंटित पूल से 200-200 मेगावाट (कुल 400 मेगावाट) बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराई जाए। इस अनावंटित बिजली की आपूर्ति जून से ही प्रारंभ हो गयी है। गत दिनों राजस्थान को छत्तीसगढ़ में फंसा 4 लाख मीट्रिक टन (लगभग 100 रैक्स) कोयले की आपूर्ति का निर्णय भी हुआ था। इस कोयले से प्रदेश के पावर प्लांट्स में कोयले के भंडारों में बढोतरी के साथ ही आमजन को पर्याप्त बिजली की सुनिश्चितता हुई।

मरुधरा की तस्वीर और तकदीर बदल रही
प्रधानमंत्री कुसुम योजना
ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बन रहा राजस्थान

नरेन्द्र सिंह शेखावत
सहायक जन सम्पर्क अधिकारी

नीयत साफ, नजर में विकास और नजरिये में नवाचार हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं! यही कारण है कि अक्षय ऊर्जा की अकूत संभावनाओं से लबरेज मरुधरा में सूरज की तपिश वरदान साबित हो रही है। तेज धूप ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि गैर उपजाऊ और गैर उपयोगी भूमि से आय का बड़ा और बेहतर विकल्प भी बना रही है। यह कमाल है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी "प्रधानमंत्री "कुसुम योजना" का। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से शुरू हुई पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें आय का एक अतिरिक्त एवं मजबूत स्त्रोत मुहैया करवाने के साथ-साथ प्रसारण एवं वितरण के दौरान बिजली छीजत में कमी लाना भी है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के त्वरित फैसले, 1.5 लाख करोड़ से अधिक का होगा निवेश

राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार त्वरित फैसले ले रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य हुए एमओयू-पीपीए के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास में 1.60 लाख करोड़ के निवेश से 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा इस संबंध में साइट विजिट की जा चुकी है। वहीं,

कोटपूतली के गांव भालोजी में हुआ सौर ऊर्जा महाअभियान का सूर्योदय

राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजना के अंतर्गत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील भालोजी गांव में 1 अप्रेल 2021 को ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ। परियोजना की स्थापना के लिए विद्युत क्रय अनुबंध गत 2 सितम्बर को जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम तथा देवकरण यादव के मध्य 25 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। भालोजी गांव में इस परियोजना का निर्माण 3.50 एकड़ भूमि पर किया गया हैं और 1 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण लगभग 3.70 करोड़ की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गंभीर प्रयासों एवं संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि पीएम-कुसुम कंपोनेंट 'बी' के तहत अब तक प्रदेश के 70 हजार से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है।

किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति के लिए मिशन मोड पर करें काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सिंचाई हेतु दिन में बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा पीएम कुसुम योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए मिशन मोड पर काम किया जाए।

भविष्य की मांग पर आधारित कार्ययोजना बने

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आगामी 10 वर्ष की मांग को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनानी चाहिए जिससे भविष्य की मांग को वर्तमान के प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप पर सोलर प्लांट के इंस्टालेशन के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिससे भविष्य में इन कार्यालयों में होने वाले बिजली व्यय को शून्य किया जा सकेगा।

राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के बढ़ते कदम

केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 325 मेगावाट एवं 2020-21 में 875 मेगावाट क्षमता प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजना के तहत आवंटित की गई थी। जिसके तहत योजनातंर्गत प्राप्त पात्र आवेदकों में से कुल 623 किसानों लेटर ऑफ अवार्ड जारी किये। इनमें से 602.5 मेगावाट क्षमता के कुल 489 प्रकरणों में बिजली खरीद समझौता पत्र हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। 14 जून 2024 तक 187.5 मेगावाट क्षमता के कुल 141 प्रोजेक्ट की स्थापना कर उन्हें ग्रिड से सफलतापूर्वक जोड़ा भी जा चुका है। वहीं, शेष परियोजनाओं को भी 30 सितंबर 2024 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए में किसानों 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट दर पर संबंधित डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद की जा रही है।

संवर रही किसानों की किस्मत

सौर ऊर्जा को बढावा देने के उद्देश्य से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना संचालित है कुसुम योजना के तहत जिन कृषकों के विद्युत कृषि कनेक्शन स्थापित नहीं है तथा डीजल आधारित पम्प सेट पर निर्भर है उन कृषकों हेतु कम्पोनेंट- बी के तहत ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कृषकों के खेतों पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत आवेदक को 60 फीसदी अनुदान का प्रावधान है जिसमें 30 फीसदी अनुदान राज्य तो वहीं 30 फीसदी अनुदान केन्द्रीय मद से मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 45000 रुपये प्रति कृषक प्रति संयंत्र अनुदान का भी अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राजस्थान में अब तक कुल 11 लाख 565 सौलर पंप की स्थापना की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान

राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व अग्रणी बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हैक्टेयर तथा फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

बीकानेर जिले में एक-एक हजार मेगावाट के दो तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जायेंगा। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (केन्द्र सरकार) की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत 3 चरणों में विकसित किये जायेंगे। साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भड़ला में भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।

प्रदेश में पेट्रोल–डीजल पर

2 प्रतिशत वैट कटौती, आमजन को मिली राहत

सीमावर्ती जिलों में तस्करी पर लगाम

राजपाल लम्बोरिया
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 14 मार्च, 2024 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 प्रतिशत वेट कटौती की घोषणा की। जिससे राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई। जिससे न केवल कृषकों और आमजन को बल्कि परिवहन व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों को भी फायदा मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें राज्य में कम होने से सीमावर्ती राज्य पंजाब और हरियाणा से पेट्रोल और डीजल की तस्करी में भी गिरावट आई है। वर्तमान में कीमतों में अधिक अंतर ना होने तथा पंजाब, हरियाणा से परिवहन लागत बढ़ने, पुलिस की नाकाबंदी और चौकसी की वजह से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिले में तस्करी पर लगाम लगी है।

तस्करी पर लगाम, डीजल की बिक्री में 65 फीसदी बढ़ोतरी

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जिला इकाई के अध्यक्ष श्री पतराम भांभू ने बताया कि 1 अप्रैल से 31 अप्रैल 2023 की तुलना में 1 अप्रैल से 31 अप्रैल 2024 तक डीजल की बिक्री में 65 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। सीमावर्ती हनुमानगढ़ जिला पूरे देश में बढ़ोतरी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है, इसका मुख्य कारण सीमावर्ती क्षेत्र में अत्यधिक मांग तथा वैट में कटौती के चलते तस्करी पर रोक लगना है। हरियाणा और राजस्थान में डीजल के दामों में अत्यधिक अंतर नहीं रहने पर हरियाणा से होने वाली 90 फीसदी से अधिक तस्करी पर रोक लगी है।

मांग बढ़ी तो दुबारा शुरू किया पेट्रोल पम्प

हनुमानगढ़ जंक्शन में पेट्रोल पम्प एजेंसी के मालिक मुश्ताक जोईया बताते है कि अधिकतर किसान सस्ता होने की वजह से हरियाणा और पंजाब से तस्करी किए हुए डीजल को खरीदते थे। इसलिए बिक्री नहीं होने की वजह से उन्हें फरवरी, 2024 में पम्प को बंद करना पड़ा। वो राज्य सरकार का आभार प्रकट करते हुए बताने लगे कि 2 प्रतिशत वैट कम करने से डीजल की मांग बढ़ने लगी तो उन्होंने पेट्रोल पम्प को अप्रैल, 2024 से दुबारा शुरू कर दिया। अब उनकी बिक्री अच्छी है। तस्करी के रुकने से ना केवल किसान बिना मिलावट का डीजल खरीद रहे है बल्कि सस्ता भी खरीद रहे हैं।

राज्य सरकार पर 1500 करोड़ का भार

राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता को पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर बड़ी राहत दी गई। पेट्रोल-डीजल की घटी हुई कीमतें 15 मार्च, 2024 सुबह 6 बजे से लागू हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ओर से दूसरी कैबिनेट बैठक में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया गया। पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपये का भार का आकलन किया गया।

ढाई महीने में 90 फीसदी तस्करी के मामलों में गिरावट

हनुमानगढ़ जिले के जिला रसद अधिकारी श्री सुनील घोड़ेला ने बताया कि जनवरी से मार्च, 2024 तक कई बड़े तस्करों को पकड़ा गया था, एक प्रकरण में ही 80 हजार लीटर पेट्रोल और डीजल जब्ती की गई थी। मार्च के बाद जून, 2024 तक तस्करी के मामलों में गिरावट आई है। राज्य सरकार द्वारा कीमतें कम करने से तस्करी में कमी दर्ज हुई है।

कृषकों के खर्चे में हुई कमी, मुनाफा बढ़ा

श्री गंगानगर जिले के सीमावर्ती गांव करड़वाल के रहने वाले युवा कृषक श्री निशांत और श्री हरबंश सिंह ने बताया कि सस्ता मिलने की वजह से अधिकतर किसान तस्करी से लाया हुआ मिलावट वाला डीजल इस्तेमाल करते थे, जिससे ट्रैक्टर के रख-रखाव का खर्चा बढ़ जाता था। अब प्रदेश में डीजल सस्ता होने की वजह से नजदीकी डीजल स्टेशन से ही भरवाते है। खर्चे में कमी आई है तथा आमदनी में बढ़ोतरी हुई है।

Empowering India : Start Up India and Stand Up India

"From Ideas to Impact: The Collective Force of Start Up India and Stand Up India"

Rakshita Yadav, APRO

India, with its burgeoning population and a vibrant entrepreneurial spirit, has been steadily emerging as a hub for innovation and business ventures. Two flagship initiatives, by the Government of India that are "Start Up India" and "Stand Up India," have played pivotal roles in fostering this entrepreneurial ecosystem by empowering entrepreneurs and marginalized sections of society. These initiatives not only aim to boost economic growth but also strive for inclusive development, ensuring that opportunities are accessible to all strata of society.

While Start Up India and Stand Up India target different demographics, their objectives converge in promoting entrepreneurship and fostering economic growth. By creating an enabling environment for innovation and enterprise creation, these initiatives complement each other, contributing to a more inclusive and dynamic economy.

Start Up India : Nurturing Innovation

Launched in 2016 by Prime Minister Narendra Modi, Start Up India aims to cultivate an environment conducive to the growth of start-ups. It offers a slew of benefits and incentives to budding entrepreneurs, streamlining bureaucratic processes, and providing financial support. The initiative focuses on three crucial aspects: simplifying procedures for company registration, taxation and compliance along with providing extensive through a dedicated helpline and online portal.

Access to finance is vital for the survival and growth of start-ups. The initiative facilitates funding additionally, start-ups enjoy tax benefits, exemptions, and easier access to loans under various government schemes. These concerted efforts have borne fruit, making India to become one of the world's fastest-growing start-up ecosystems.

Stand Up India : Empowering Entrepreneurs

While Start Up India targets entrepreneurs across various sectors, Stand Up India focuses specifically on empowering Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) and women. Launched in 2016 by Prime Minister Narendra Modi, this initiative aims to provide financial assistance of Rs. 10 lakhs to 1 crore to underprivileged sections of society for setting up greenfield enterprises.

Stand Up India offers various training programs, workshops, and skill development initiatives to equip aspiring entrepreneurs with the necessary tools to run successful businesses. Stand Up India provides handholding support and mentoring services to guide aspiring entrepreneurs through the difficulties of business establishment. Through these concerted efforts, Stand Up India aims to foster economic empowerment and social inclusion of marginalized sections of society.

In conclusion, Start Up India and Stand Up India represent significant milestones in India's journey towards fostering entrepreneurship and inclusive growth. These initiatives are not only transforming the entrepreneurial landscape but also paving the way for a more equitable and prosperous future.

फार्म–1

(नियम 3 देखिये)

1.	समाचार पत्रिका का नाम	:	राजस्थान सुजस
2.	समाचार पत्रिका की भाषा	:	हिन्दी
3.	प्रकाशन का स्थान	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर
4.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
5.	मुद्रक का नाम	:	सुनील शर्मा
	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
6.	पता प्रेस	:	रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर प्रिन्ट 'ओ'लैण्ड, 22 गोदाम, जयपुर मै. कृष्णा प्रिंटर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस, रामनगर, जयपुर
7.	सम्पादक का नाम	:	अलका सक्सेना
	क्या भारतीय नागरिक है	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
	पता	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सचिवालय, जयपुर

8. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं, सुनील शर्मा एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

सुनील शर्मा

पीएम श्री विद्यालय

सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण लक्ष्य के साथ उत्कृष्ट परिणाम

प्रदेश में पीएम श्री योजना में संचालित विद्यालय गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में संचालित 402 विद्यालयों के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा परिणाम इस योजना की सफलता की बानगी हैं।

पीएमश्री योजना में सत्र 2023-24 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान संकाय में 98 प्रतिशत से अधिक, कला संकाय में 97 प्रतिशत से अधिक और वाणिज्य संकाय में 99 प्रतिशत से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस योजना का उद्देश्य आनन्ददायी वातावरण में विद्यार्थियों के साथ खेल आधारित, पूछताछ, खोज उन्मुख एवं विद्यार्थी केन्द्रित समग्र एवं एकीकृत शिक्षण विधियों का प्रयोग कर उनके अद्यतन कौशलों से सज्जित समग्र व सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करना है।

सत्र 2023-24 में पीएम श्री योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत संचालित 402 विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक परीक्षा के विज्ञान संकाय में कुल विद्यार्थी 9972 प्रविष्ट हुए। इनमें से प्रथम श्रेणी में 8280 विद्यार्थियों सहित परिणाम 98.17 प्रतिशत रहा। कला संकाय में कुल 20073 प्रविष्ट विद्यार्थियों में से 11415 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और परिणाम 97.61 प्रतिशत रहा। वाणिज्य संकाय में 1044 प्रविष्ट विद्यार्थियों में से प्रथम श्रेणी में 685 विद्यार्थियों सहित परिणाम 99.04 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार माध्यमिक परीक्षा में 25243 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए जिनमें से प्रथम श्रेणी में 11040 विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के साथ ही परिणाम 90 प्रतिशत रहा।

सपना के सपनों को मिले पंख

डीग जिले की सीकरी तहसील के एक छोटे से गांव इमलारी की हरिजन बस्ती की रहने वाली सपना कुमारी ने सत्र 2023-24 में कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 84.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विपरीत परिस्थितियों में रहकर सफलता की कहानी लिखी। सपना ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि प्रयास मन से किये जाएं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सपना ने यह सफलता निवास से 2.5 कि.मी. दूर स्थित पी. एम. श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुलपाडा में अध्ययनरत रहकर प्राप्त की है।

सपना एक छोटे से घर में चार भाई बहन, माता पिता समेत कुल 6 लोगों के साथ निवास करती है। सपना का परिवार साफ-सफाई का काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। पढ़ाई का बहुत सारा समय घर के कामों में निकल जाता है जिससे पढ़ाई के लिए दिन में बहुत कम समय निकल पाता है। मां के काम न कर पाने के कारण सपना को साफ-सफाई के पारिवारिक कार्य तथा अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाना पड़ता है।

इस सबके बावजूद सपना का कक्षा 8 के साथ होने वाली NMMS परीक्षा में चयन हुआ, यह सपना के पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सपना पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेती है। सपना की पढ़ाई के प्रति इस लगन को देखते हुए सपना की विद्यालय फीस, बोर्ड परीक्षा फीस, यूनिफॉर्म, नोटबुक, पेन व अन्य पाठ्य सामग्री विद्यालय स्टाफ द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। निश्चित ही पीएम श्री विद्यालय विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशलों से सुसज्जित कर "भविष्य के नागरिकों" के रूप में का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. नीरु पोटलिया
सहायक निदेशक, आरएसईसी, जयपुर

पूंछरी का लौठा

गिरिराज जी (गोवर्धन) की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं। परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान के भरतपुर (नवगठित डीग) जिले में आता है। इसमें पूंछरी का लौठा मंदिर पड़ता है, राजस्थान के श्रद्धालु पूंछरी का लौठा से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है कि वे पूंछरी का लौठा के दर्शन कर अपनी हाजिरी लगाएं। इसके आस-पास अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग के शिव, त्रेता के हनुमान, द्वापर के मधुमंगल और कलयुग के पूंछरी का लौठा हैं। इन्हें श्री गिरिराज महाराज के चरण भी माना जाता है।

स्थानीय कहावत 'धन्य-धन्य पूंछरी की लौठा, अन्न खाए न पानी पिए पड़ी रहे सिलौटा' में इनके स्वभाव का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार 'धन्यवाद है पूंछरी के लौठा को जो अन्न भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते और शिला की तरह एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं'।

आलेख और छाया : **हरिओम सिंह गुर्जर,** संयुक्त निदेशक

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

सरिस्का

बढ़ा बाघों का कुनबा

विश्व विख्यात अलवर स्थित सरिस्का अभयारण्य बाघों के बढ़ते कुनबे के कारण अब बाघों की समृद्ध नर्सरी के रूप में विकसित हो रहा है। हाल ही में बाघिन एसटी-17 के द्वारा तीन नए शावकों को जन्म देने के बाद वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब बाघों का कुनबा 43 का हो गया है जिसमें 11 नर, 14 मादा एवं 18 शावक शामिल हैं तथा इन शावकों में से 13 का जन्म पिछले चार महीनों के दौरान हुआ है। यहां की आबोहवा बाघों के फलने-फूलने के लिए उपयुक्त है और यहां प्रचुर मात्रा में भोजन व पानी की उपलब्धता है जिससे यहां के बाघ लम्बी उम्र भी जी रहे हैं। जहां बाघों की औसत आयु 12-15 साल मानी जाती है वहीं सरिस्का में बाघ 15-19 साल का औसत जीवन जी रहे हैं।

आलेख एवं छाया : **मनोज कुमार**
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, सुनील शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - श्रीमती अलका सक्सेना, मैसर्स रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, बी-3, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 33.30 रुपये • 30,000 प्रतियां